www.ghoonghatkibagawat | www.ghoonghatkibagawat | ghoonghatkibagawat37@gmail.com

घूँघट की बगावत

UP/HIN/1999/1282

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 24 अंक : 20 | गोरखपुर, 24 नवम्बर 2024 रविवार | पृष्ठ : 6 | मूल्य : 2

हारी बाजी जीतना हमें आता है...

एक दो दिन पहले तक लग रहा था कि महाराष्ट्र की लड़ाई बहुत नजदीक होगी। वहीं एक दो हफ्ते पहले तक तो लग रहा था कि प्रदेश में महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में सरकार बना लेगी। लेकिन 20 तारीख को वोटिंग के बाद कई सर्वे आए कभी महायुति को आगे दिखाया गया। लेकिन जब नतीजे आएं तो सभी की आंखें चकाचौंध से भर उठी। बीजेपी ने अभी तक महाराष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने ऐसा क्या किया है कि उसे प्रदेश में इतनी बड़ी ग्रोथ मिल गई है। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी और आरएसएस के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिला। जिसका लाभ महायुति को इस बार के चुनाव में देखने को मिला। जानकारों का कहना है कि जिस तरह से इसी साल लोकसभा चुनाव के बाद नतीजे बीजेपी के लिए चौंकाने वाले आए थे। उससे जो नैरेटिव सेट हुआ उसे बदलने के लिए आरएसएस ने खुद मोर्चा संभाल लिया था। आरएसएस ने बीजेपी के लिए पूरा जोर लगाया था। कहा जा रहा है कि इसी वजह से महाराष्ट्र में वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हुआ। आपको बताते हैं कि संघ ने महाराष्ट्र में पर्दे के पीछे रहकर कैसे काम किया।

जहां से आरएसएस की उत्पत्ति हुई और इसका मुख्यालय भी जहां स्थित है वहां कैडरों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे एक राजनीतिक और सांस्कृतिक बाजीगर क्यों बने हुए हैं। अपने वैचारिक राजनीतिक पक्ष में हवा के रुख को मोड़ने के लिए रणनीतियों के साथ हिंदुत्व के ताने बाने को सहजता से बुनने में माहिर माना जाता है। मुंबई के औद्योगिक केंद्रों से लेकर विदर्भ के कृषि क्षेत्रों तक, आरएसएस कार्यकताओं की जमीनी स्तर की लामबंदी ने हिंदू वोटों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संघ के संगठन और बीजेपी के बड़े नेता लगातार बैठके कर रहे थे। संघ के साथ वीएचपी, वनवासी कल्याण आश्रम, भारतीय मजदूर संघ के साथ भी बड़े बीजेपी नेताओं की बैठक हो रही थी। हाल ही में विपक्ष की तरफ से स्थापित जातिगत रेखाओं को तोड़कर एक नया चुनावी गणित तैयार किया है। विपक्ष के नरेटिव को तोड़ने के लिए संघ ने 13 अलग अलग ग्रुप बनाए। इनका काम ग्राउंड पर जाना और सोशल मीडिया पर विपक्ष के नैरेटिव को काउंटर करना था।

> आरएसएस ने घर-घर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हमारे सजग रहो मंत्र के साथ, संघ के नेटवर्क ने बूथ स्तर पर चुपचाप काम किया। आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि हम विशेष रूप से विदर्भ, कोंकण, मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में बिखरे हुए समुदायों को सफलतापूर्वक एकजुट कर सकते हैं, जहां जातिगत वफादारी अक्सर मतदान के पैटर्न को निर्धारित करती है।

संघ ने महाराष्ट्र की सभी विधानसभा सीटों पर घर घर जाकर कैंपेन किया। संविधान खतरे में है वाले नैरेटिव की काट घर घर संविधान से दिया गया। आरएसएस ने घर-घर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हमारे सजग रहो मंत्र के साथ, संघ के नेटवर्क ने बूथ स्तर पर चुपचाप काम किया। आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि हम विशेष रूप से विदर्भ, कोंकण, मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में बिखरे हुए समुदायों को सफलतापूर्वक एकजुट कर सकते हैं, जहां जातिगत वफादारी अक्सर मतदान के पैटर्न को निर्धारित करती है। हिंदुत्व के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके और सड़कों पर दिखाई देने वाली मुस्लिम आक्रामकता के बारे में चिंताओं को संबोधित करके, संघ ने मध्यम वर्ग के भीतर बढ़ती नापसंदगी का फायदा उठाया। यह मौन एकजुटता महत्वपूर्ण 4-5 प्रतिशत वोट स्विंग में बदल गई, जिससे भाजपा का आधार उसके पारंपरिक समर्थन आधार और गढ़ों से आगे बढ़ गया। संघ ने मराठा, आदिवासी और दलित समाज नेताओं को प्रचार में लगाया। सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग के लिए इंफ्ल्यूएंशर को अलग से टीम बनाई। संघ की इस मेहनत का असर आज नतीजों के रूप में सामने हैं।

हरियाणा चुनाव के नतीजों के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि कैसे ग्रामीण और शहरी इलाकों में आरएसएस की पैठ ने शासन और जमीनी स्तर की चिंताओं, कुछ परस्पर विरोधी जातियों के बीच की खाई को सफलतापूर्वक पाट दिया और भाजपा को अपने राजनीतिक परिणामों को आकार देने में मदद की। बेरोजगारी, जातिगत गतिशीलता या सांस्कृतिक पहचान से लेकर क्षेत्रीय असंतोष को भुनाने की संगठन की क्षमता ने इसे भाजपा के लाभ के लिए मतदाता-भावना को प्रभावित करने की अनुमति दी है। इसका व्यवस्थित और कैडर-संचालित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि मुद्दों को न केवल उठाया जाए बल्कि उनका समाधान भी किया जाए। इसी तरह, महाराष्ट्र में संघ ने राजनीतिक रूप से जटिल राज्य में रणनीतियों को पुनः व्यवस्थित करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। भाजपा की गठबंधन चुनौतियों के साथ-साथ शिवसेना और राकांपा के भीतर विभाजन के बावजूद, संघ का जमीनी कार्य मतदाताओं को एकजुट करने में सहायक रहा है। मराठा वोटों में बिखराव का भी महायुति और बीजेपी को फायदा मिला। मुंबई जैसे औद्योगिक क्षेत्रों सहित शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर, बेरोजगारी के मुद्दों, आर्थिक स्थिरता और कानून व्यवस्था के आसपास मध्यम वर्ग की चिंताओं पर जोर दिया। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना द्वारा अपनाए गए उद्योग-विरोधी और व्यापार-विरोधी रुख ने वास्तव में शहरी मतदाताओं को निराश किया था। इसके विपरीत, मुंबई पेरिफेरल रोड परियोजना और अन्य विकास जैसी पहल, जबकि लाडली बहना जैसी लक्षित नीतियां महिलाओं और शहरी गरीबों जैसे मुद्दे को टच करना लोगों को भा गया।

योगी के नेतृत्व में एक रहा यूपी, कुंदरकी-कटेहरी ने भी लिखा नया इतिहास

लखनऊ। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर बता दिया कि उन्हें योगी आदित्यनाथ का ही साथ पसंद है। प्रदेश में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में सात पर एनडीए ने जीत दर्ज की। इसमें से छह पर भारतीय जनता पार्टी और एक सीट पर एनडीए गठबंधन (रालोद) ने जीत हासिल की। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के हिस्से की कुंदरकी व कटेहरी सीट भी जीत ली। इन दोनों सीटों पर नया इतिहास लिखा गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी व रालोद प्रत्याशी के पक्ष में पांच दिन में 15 चुनावी कार्यक्रम किए। सीएम योगी ने फूलपुर, मझवा, खैर व कटेहरी में दो-दो रैली की। गाजियाबाद में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक रैली व एक रोड शो कर कमल को फिर से खिलाने की अपील की, जिस पर जनता ने मुहर लगाया। वहीं कुंदरकी व मीरापुर में भी सीएम की रैली हुई। इसका असर यह हुआ कि कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। कटेहरी में लगभग तीन दशक से अधिक समय से इस सीट पर भाजपा को जीत नहीं मिल पा रही थी, लेकिन इस बार उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कटेहरी में भी कमल ने कमाल कर दिखाया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मराज निषाद ने तीन दशक बाद यहां कमल खिलाया। धर्मराज निषाद ने न सिर्फ सपा से यह सीट छीनी, बल्कि सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा को 34514 के बड़े अंतर से हराया। वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव में कुंदरकी में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। इस सीट पर भी विधायक के सांसद चुने जाने के कारण यहां उपचुनाव हुआ। इस सीट पर भी काफी समय से समाजवादी पार्टी का कब्जा था, लेकिन 2024 में हुए उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह सीट भाजपा के खाते में गई। योगी के आह्वान पर जनता ने यहां से सपा को चारों खाने चित कर दिया। यहां के भाजपा उम्मीदवार रामवीर सिंह ठाकुर ने सपा के मो. रिजवान को काफी बड़े अंतर से पराजित किया। मझवा, फूलपुर, गाजियाबाद, खैर के साथ ही मीरापुर में भी रैलियों से चल रही योगी-योगी की गूंज शनिवार को जीत के बाद और तेज होती गई। मीरापुर में रालोद व अन्य सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। मझवा में विनोद बिंद, फूलपुर से प्रवीण पटेल, गाजियाबाद से अतुल गर्ग, खैर से अनूप प्रधान वाल्मीकि व मीरापुर से चंदन चौहान के सांसद चुने जाने के उपरांत यहां उपचुनाव कराए गए। इन सीटों को बरकरार रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अन्य सीटों पर जीत हासिल की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेहनत का ही प्रतिफल है कि समाजवादी पार्टी के घर करहल में भी सपा की जीत का अंतर काफी कम हुआ। 2022 आमचुनाव में सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव ने यहां 67504 वोटों से जीत हासिल की थी, जो 2024 उपचुनाव में घटकर महज 14725 वोट पहुंच गई। तेज प्रताप यादव को यहां से 104304 वोट मिले। भाजपा के अनुजेश यादव ने 89579 वोट प्राप्त किया। वहीं सीसामऊ में 2022 में सपा के इरफान सोलंकी ने 12266 वोटों से जीत हासिल की। उपचुनाव में सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने 69714 वोट पाकर 8564 वोट से जीत दर्ज की। यहां से भाजपा के सुरेश अवस्थी को 61150 वोट मिले।

सात सीटों पर जीत व अंतर

कुंदरकी- रामवीर सिंह ठाकुर गाजियाबाद- संजीव शर्मा- 96946 (69351 से जीत) फूलपुर- दीपक पटेल- 78289 (11305 से जीत) मझवां- सुचिस्मिता मौर्या- 77737 (4922 से जीत) कटेहरी- धर्मराज निषाद- 104091 (34514 से जीत) खैर- सुरेंद्र दिलेर झ 100181 (38393 से जीत) मीरापुर- मिथिलेश पाल (रालोद)- 84304 (30796 से जीत)

▶ पहाड़ी गाय शामिल हुई पशु गणना में

गाय के साथ बेसहारा पशुओं और आवारा कुत्तों का भी डाटा एकत्रित किया जा रहा

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग ने पहली बार राज्य की हिमाचली पहाड़ी गाय 'गौरी' को भी पशुगणना में शामिल किया है। इससे पहले विभाग द्वारा इनका आंकड़ा नहीं जुटाया जाता था। केंद्र सरकार की पहल पर 2024 की पशुगणना में हिमाचली पहाड़ी गाय के साथ बेसहारा पशुओं और आवारा कुत्तों का भी डाटा एकत्रित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पशुओं की संख्या का सही आकलन कर योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। गणना से सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशुओं और आवारा कुत्तों की संख्या स्पष्ट होगी। इन आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार से टीकाकरण स्टॉक और योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। हालांकि इससे पहले न विभाग को जानकारी होती थी कि सड़कों पर कितने पशु बेसहारा और आवारा कुत्ते घूम रहे हैं और न ही पता होता था कि कौन सड़कों पर पशुओं को बेसहारा छोड़ रहा है।

> केंद्र की ओर से पहली बार प्रदेश की देसी गाय का आंकड़ा एकत्रित किया जाएगा। साथ ही पहली बार बेसहारा पशुओं और आवारा कुत्तों का भी आंकड़ा इकट्ठा किया जा रहा है। इससे केंद्र सरकार के पास प्रदेश के पशुओं की संख्या का सही आंकड़ा पहुंचेगा।
> -डॉ. संदीप मिश्रा, नोडल अधिकारी, पशुपालन विभाग, कांगड़ा

अब विभाग की ओर से की जा रही गणना में सड़कों पर घूम रहे पशुओं का आंकड़ा एकत्रित हो जाएगा, जिससे कि प्रदेश में केंद्र की ओर से विभिन्न योजनाओं के तहत टीकाकरण का प्रबंध भी किया जाएगा। इससे पहले केंद्र की ओर से 2019 की पशुगणना के अनुसार ही विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदेश में टीकाकरण का स्टॉक और टारगेट भेजे जाते थे। उल्लेखनीय है कि हिमाचल सरकार ने हिमाचली पहाड़ी गाय को ह्यगौरीह्न नाम दिया है और इसी नाम से इसके संरक्षण के लिए इस–ाका पंजीकरण भी करवाया या है। जिला कांगड़ा के 30 तहसीलों में 4006 गांव हैं, जहां 609 फार्मासिस्ट, 95 सुपरवाइजर और दो जिला स्तरीय नोडल अधिकारी आंकड़े जुटा रहे हैं। नगरोटा तहसील ने अपना डाटा जिला नोडल अधिकारी को सौंप दिया है, जो आगे राज्य नोडल अधिकारी को भेजा जाएगा। प्रदेशभर में यह प्रक्रिया 25 फरवरी तक पूरी कर ली जाएगी।

नशीले पदार्थ के साथ पांच गिरफ्तार

बेंगलुरु। पुलिस ने यहां अलग-अलग अभियानों में पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और छह करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ की दो बड़ी खेप पकड़ी है। अधिकारियों ने गत शुक्रवार को यह जानकारी दी।पुलिस को संदेह है कि बेंगलुरु और उसके आसपास के क्षेत्र में नये साल के जश्न के मौके पर मादक पदार्थों की आपूर्ति के लिए उसे शहर में तस्करी कर लाया जा रहा हो। पहले मामले में, केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) पुलिस ने सोलादेवनहल्ली थानाक्षेत्र में एमडीएमए क्रिस्टल , कोकीन और एक्स्टसी गोलियों जैसे प्रतिबंधित मादक पदार्थों की बिक्री में कथित रूप से शामिल दो विदेशियों से जब्त की। पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने यहां संवाददाताओं से कहा, हमने 1.5 किलोग्राम एमडीएमए क्रिस्टल, 202 ग्राम कोकीन और 12 एक्स्टसी गोलियां जब्त की हैं। हमने दो मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। मादक पदार्थ की कीमत करीब तीन करोड़ रुपये है।

नहीं चला राहुल मैजिक

शनिवार का दिन इंडिया ब्लॉक के लिए मिला-जुला साबित हुआ। महाराष्ट्र के झटके को देखते हुए झारखंड में जीत कांग्रेस के मूड को छोड़ा बैलेंस करने के लिए ठीक रही। नतीजों का इंडिया ब्लॉक महाराष्ट्र के एमवीए घटकों और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी के ट्रैक रिकॉर्ड और चुनाव जीतने की क्षमता पर गहरा प्रभाव पड़ना तय है। अधिकांश अन्य राज्यों के विपरीत, महाराष्ट्र कांग्रेस के पास एक आक्रामक और मजबूत संगठन है। यही वजह है कि राज्य में कांग्रेस नेता हाथ-पैर मारते हैं और पार्टी के लिए अधिक सीटों पर जोर देते हैं। इतना ही नहीं, सरकार बनाने की उम्मीद में कांग्रेस की ओर से मांग की गई है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उन्हें ही बैठाया जाए. इससे महा विकास अघाड़ी के सहयोगी परेशान हो गए, जिन्होंने महसूस किया कि ध्यान केंद्रित रहना महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र जनादेश के बाद सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को ऐतिहासिक जीत मिली और एमवीए की राज्य में सत्ता में वापसी की उम्मीदें खत्म हो गईं, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भाजपा कार्यकताओं को संबोधित करने वाले हैं। इस बीच, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव नतीजों पर असंतोष जताते हुए कहा कि ये नतीजे अप्रत्याशित हैं। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी जनादेश का विश्लेषण करेगी।

माना जाता है कि सीएम की कुर्सी की लड़ाई उन कारणों में से एक है जिसके कारण उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा क्योंकि कैडर उनकी लड़ाई में फंस गया था। वहीं झारखंड में इंडिया ब्लॉक ने आधे का आंकड़ा पार कर लिया और जैसे-जैसे गिनती आगे बढ़ी, उसने अपनी बढ़त बढ़ा ली, जिससे राज्य में सत्ता में वापसी की भाजपा की उम्मीदों को झटका लगा। झारखंड में इंडिया ब्लॉक 57 सीटों पर आगे है जबकि एनडीए 23 सीटों पर आगे है। इस बीच, शाम 5 बजे तक 236 सीटों पर बढ़त के साथ महायुति महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने को तैयार है। एमवीए 48 सीटों पर आगे चल रही है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 है जबकि झारखंड में यह 41 है। महायुति में इस समय तक बीजेपी 134, शिवसेना 57 और एनसीपी 41 सीटों पर आगे है, जबकि एमवीए में शिवसेना यूबीटी 20, कांग्रेस 15 और एनसीपी-एसपी 9 सीटों पर आगे चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6.30 बजे के बाद बीजेपी मुख्यालय जाएंगे और पार्टी नेताओं और कार्यकताओं को संबोधित करेंगे। मतगणना के शुरूआती दौर में एनडीए आगे चल रही थी, लेकिन झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व वाले इण्डिया गुट ने विपक्षी गठबंधन को पीछे छोड़ दिया। तब से सत्ताधारी गठबंधन ने अपनी बढ़त बढ़ा ली है।

सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से आठ कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 1.55 लाख करोड़ रुपए बढ़ा

नई दिल्ली। सेंसेक्स की शीर्ष 10 कंपनियों में से आठ के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में पिछले सप्ताह कुल मिलाकर 1,55,603.45 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। एचडीएफसी बैंक और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को सबसे ज्यादा लाभ हुआ। बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1,536.8 अंक या 1.98 प्रतिशत के लाभ में रहा। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 374.55 अंक या 1.59 प्रतिशत चढ़ गया। शुक्रवार को सेंसेक्स 1,961.32 अंक या 2.54 प्रतिशत उछलकर 79,117.11 अंक पर बंद हुआ।

एनएसई निफ्टी भी 557.35 अंक या 2.39 प्रतिशत बढ़कर 23,907.25 अंक पर पहुंच गया। शीर्ष 10 कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के बाजार मूल्यांकन में भी गिरावट आई। अन्य कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में इजाफा हुआ।

समीक्षाधीन सप्ताह में एचडीएफसी बैंक का बाजार मूल्यांकन 40,392.91 करोड़ रुपये बढ़कर 13,34,418.14 करोड़ रुपये हो गया। सबसे अधिक लाभ एचडीएफसी बैंक को ही हुआ। टीसीएस की बाजार हैसियत 36,036.15 करोड़ रुपये बढ़कर 15,36,149.51 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। आईसीआईसीआई बैंक का मूल्यांकन 16,266.54 करोड़ रुपये बढ़कर 9,01,866.22 करोड़ रुपये पर और इन्फोसिस का 16,189.33 करोड़ रुपये बढ़कर 7,90,151.83 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाजार पूंजीकरण में 13,239.95 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई और यह 5,74,569.05 करोड़ रुपये रहा।

आईटीसी की बाजार हैसियत 11,508.91 करोड़ रुपये बढ़कर 5,94,272.93 करोड़ रुपये हो गई। भारती एयरटेल का मूल्यांकन 11,260.11 करोड़ रुपये बढ़कर 8,94,068.84 करोड़ रुपये पर और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की बाजार हैसियत 10,709.55 करोड़ रुपये बढ़कर 7,28,293.62 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। इस रुख के उलट भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का मूल्यांकन 11,954.24 करोड़ रुपये घटकर 5,62,545.30 करोड़ रुपये रह गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 2,368.16 करोड़ रुपये घटकर 17,13,130.75 करोड़ रुपये रह गया। शीर्ष 10 कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर कायम रही।

उसके बाद क्रमशः टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, इन्फोसिस, भारतीय स्टेट बैंक, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एलआईसी का स्थान रहा।

पांच सीटों पर खिला कमल

राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या बढ़कर 119 हो गई है। उपचुनाव में बीजेपी पांच सीटें जीत गई है। इनमें सलूंबर, खींवसर, झुंझुनूं, देवली-उनियारा और रामगढ़ सीट शामिल है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या बढ़कर 119 हो गई है। उपचुनाव में बीजेपी पांच सीटें जीत गई है। इनमें सलूंबर, खींवसर, झुंझुनूं, देवली-उनियारा और रामगढ़ सीट शामिल है। झुंझुनूं में बीजेपी की जीत इस मायने में भी अहम है। क्योंकि बीजेपी यहां दशकों से चुनाव नहीं जीती थी। बीजेपी ने अखिरी बार साल 2003 में यह सीट जीती थी। इसके बाद से यह सीट कांग्रेस के टिकट पर बृजेंद्र ओला जीतते रहे। इसलिए यह यह सीट कांग्रेस और ओला परिवार का गढ़ मानी जाती थी। अब बीजेपी के राजेंद्र भांबू ने बृजेंद्र ओला के पुत्र और कांग्रेस प्रत्याशी अमित ओला को 42,828 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव हरा दिया है।

खास बात यह है कि 2023 के विधानसभा चुनावों में भी राजेंद्र भांबू ने यहां बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में भांबू को कुल 42,407 वोट मिले थे। यानी भांबू को 2,023 में जितने वोट मिले थे, उससे ज्यादा वोटों के अंतर से उन्होंने उपचुनाव में जीत दर्ज की है। हालांकि, उनकी जीत में निर्दलीय राजेंद्र गुढ़ा का भी बड़ा रोल रहा है। राजेंद्र गुढ़ा ने कांग्रेस के वोट काटने का काम किया। खींवसर के नतीजे भी चौंकाने वाले रहे। हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल यहां बीजेपी के रेवतराम डांगा से चुनाव हार गए। इसकी बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने यहां हनुमान को हरवाने के लिए बीजेपी में वोट शिफ्ट करवाए हैं।

साल 2023 में रेवतराम को खींवसर में करीब 77 हजार वोट मिले थे। इस बार उन्होंने एक लाख आठ हजार 628 वोट लिए हैं। यानी पिछले चुनावों के मुकाबले उन्होंने करीब 41 हजार से ज्यादा वोट लिए। वहीं, उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी कनिका बेनीवाल को 92,727 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी रतन चौधरी की यहां जमानत जब्त हो गई, उन्हें सिर्फ 5,454 वोट मिले हैं। देवली-उनियारा सीट भी बीजेपी ने कांग्रेस से छीन ली है। यहां बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर 41,121 वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं। हालांकि, इसकी बड़ी वजह थप्पड़ कांड के आरोपी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा रहे। थप्पड़ कांड के बाद पूरे उनियारा में नरेश को लेकर मीणा वोटों का कंसोलिडेशन हो गया। इससे कांग्रेस के केसी मीणा नतीजों में तीसरे नंबर पर आ गए। नरेश 59,478 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सबसे रोचक मुकाबला सलूंबर सीट पर देखने को मिला। यहां 21 राउंड तक बीएपी आगे चल रही थी। लेकिन आखिरी राउंड मे बाजी पलट गई और बीजेपी की शांता अमृतलाल मीणा 1,285 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गईं। सलूंबर एक मात्र सीट थी, जो उपचुनाव से पहले बीजेपी के पास थी। दौसा में मैच फिक्स तो हुआ, लेकिन कांग्रेस के डीडी बैरवा के पक्ष में।

बीजेपी के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा दौसा उपचुनाव हार गए। हारने के साथ ही जगमोहन ने बयान दिया, जब अपने ही बेवफा हो जाएं तो कोई क्या करे। डीडी बैरवा ने 2,300 वोटों के अंतर से जगमोहन को चुनाव हरा दिया। रामगढ़ सीट पर भी बार-बार समीकरण बदलते रहे। शुरूआत में कांग्रेस के आर्यन जुबेर 10 हजार वोटों तक की लीड़ ले गए थे। इसके बाद बीजेपी के सुखवंत ने वापसी की और राउंड पूरे होते-होते सुखवंत ने 13,614 वोटों से मुकाबला जीत लिया।

अनाथ-गरीब बच्चों के लिए खुलेगा निशुल्क इंग्लिश मीडियम स्कूल और छात्रावास, प्रमाणसागरजी

केकड़ी। दिगंबर जैन समाज के श्रेष्ठीरत्न, प्रमुख मार्बल व्यवसायी अशोक पाटनी और चांपानेरी के दिल्ली निवासी नेमीचंद जैन के आग्रह पर, इंदौर में विराजमान प्रख्यात दिगंबर जैन संत मुनि प्रमाणसागरजी महाराज ने केकड़ी जिले के चांपानेरी गांव में निःशुल्क अंग्रेजी माध्यम स्कूल और छात्रावास खोलने की घोषणा की। उन्होंने मध्यप्रदेश के सागर जिले के लोहारी गांव में भी ऐसा ही स्कूल और छात्रावास खोलने की घोषणा की। इन दोनों स्थानों पर अनाथ और गरीब बच्चों को आधुनिक शिक्षा के लिए निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। मुनि संघ से जुड़े अजय जैन ने बताया कि ये स्कूल महाराज की प्रेरणा से जनकल्याण कार्यों में सक्रिय गुणायतन संस्था द्वारा संचालित किए जाएंगे।

इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए गुणायतन परिवार की ओर से कार्य योजना तैयार की जा रही है। योजना के अनुसार, स्कूल की क्षमता एक हजार विद्यार्थियों के अध्ययन की होगी। इसमें सभी समाजों के जरूरतमंद बच्चों को प्रवेश देकर निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। खासतौर पर गरीब परिवारों के उन बच्चों को जो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण अच्छे स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर पाते। उन्हें अंग्रेजी माध्यम की निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी।

उन्होंने यह भी बताया कि शिक्षा, समाज की उन्नति और नई पीढ़ी के रचनात्मक व्यक्तित्व निर्माण का मुख्य आधार है। लेकिन, प्रतिस्पर्धा के इस युग में आर्थिक तंगी के कारण गरीब और असहाय बच्चे आधुनिक और तकनीकी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए जनकल्याण की भावना से प्रेरित होकर संत शिरोमणि दिवंगत दिगंबर जैन आचार्य श्री विद्यासागरजी महाराज के संघ द्वारा देशभर में बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थान संचालित किए जा रहे हैं। इस प्रकल्प के अंतर्गत आचार्य विद्यासागर मुनि संघ के मुनिपुंगव सुधासागरजी महाराज और मुनि प्रमाणसागरजी महाराज द्वारा यह कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। मुनि प्रमाणसागरजी महाराज की इस घोषणा के बाद चांपानेरी गांव के निवासियों में हर्ष व्याप्त है। ग्रामीणों ने स्कूल खोलने के प्रयास करने वाले नेमीचंद जैन और उनके परिवार का अभिनंदन किया।

डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए एग्रीस्टैक परियोजना : टंकराम वर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ अब डिजिटल कृषि की ओर अग्रसर है। एग्रीस्टैक परियोजना के तहत डिजिटल कृषि को बढ़ावा मिलेगी। राज्य के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए एग्रीस्टैक परियोजना संचालित की जा रही है। इसके तहत ग्राम का जियो रिफ्रेसिंग सर्वेक्षण नक्शा, राजस्व संबंधित अधिकार अभिलेख और डिजिटल फसल सव-ेक्षण का काम किया जा रहा है। पॉयलेट प्रोजेक्ट के तहत 20 जिलों में जियो रिफ्रेसिंग तकनीक से सर्वे कर नक्शा तैयार करने का काम चल रहा है। अब तक 10 हजार 243 गांवों में यह काम पूरा कर लिया गया है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में एग्रीस्टेक परियोजना के तहत डिजिटल फसल सर्वेक्षण तीन जिलों में पूर्ण रूप किया जा रहा है। 16 जिलों की एक-एक तहसील में भी फसल सर्वेक्षण किया जा रहा है। आगामी दिनों में राज्य के सभी जिलों में डिजिटल फसल सर्वे का काम होगा।

इस परियोजना में कृषकों का पंजीयन किया जा रहा है। इसके माध्यम से कृषकों को केन्द्र और राज्य सरकार के योजनाओं का पारदर्शी ढंग से लाभ मिलेगा। मोबाइल एप के माध्यम से पंजीयन स्वयं किसान और युवा कर सकेंगे। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर, वेबसाइट के माध्यम से पटवारी कर सकेंगे। कृषक पंजीयन के लिए कॉमन सर्विस सेंटर में प्रत्येक ई-केवाईसी के लिए 15 रुपये की दर निर्धारित की गई है।

किसानों के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र है। इससे किसानों को कई तरह की सुविधाएं मिलेगी। सस्ता ऋण, अच्छी क्वालिटी के कृषि इनपुट, स्थानीय सलाह, बाजारों तक आसान पहुंच, सरकारों को किसानों के लिए योजनाएं बनाने और लागू करने में मदद मिलेगी। एग्रीस्टेक के तहत, किसानों की सभी जानकारी एक जगह इकट्ठा की जाएगी। इसमें उनकी पहचान, भूमि रिकॉर्ड, आय, बीमा, ऋण, फसल विवरण और राजस्व इतिहास शामिल होगा। किसानों की पहचान के लिए, उन्हें एक डिजिटल आईडी दी जाएगी, जो आधार कार्ड की तरह काम करेगी। इस आईडी में किसानों से जुड़े कई तरह के डेटा होंगे।

अडानी समूह पर रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर डोटासरा ने उठाए गंभीर सवाल

जयपुर । राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बयान जारी कर गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर लगे दो हजार करोड़ रुपये की रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। अमेरिकी प्रतिभूति विनिमय आयोग की जांच के हवाले से उन्होंने कहा कि अडानी समूह ने भारत में उच्च-मूल्य वाले सौर ऊर्जा अनुबंधों को हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की योजना बनाई थी। डोटासरा ने बताया कि अमेरिकी अभियोग के अनुसार, 2020 से 2024 के बीच अडानी समूह ने रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक का लाभ अर्जित किया। यह मामला अमेरिकी कानून, विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम और संघीय प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन है।

डोटासरा ने कहा कि अडानी समूह की गतिविधियों के कारण उपभोक्ताओं को महंगी दरों पर सौर ऊर्जा खरीदनी पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि कोयले और बिजली उपकरणों के दाम बढ़ाकर दिखाने से भी बिजली की दरें दोगुनी हो गईं। इसके अलावा, अडानी समूह ने शेयर बाजार में हेरफेर कर भारतीय निवेशकों को नुकसान पहुंचाया।

कांग्रेस ने सेबी की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की समयसीमा के बावजूद सेबी 20 महीने बाद भी जांच पूरी नहीं कर पाई। डोटासरा ने आरोप लगाया कि सेबी की अध्यक्ष माधबी बुच के अडानी के साथ संबंधों के कारण जांच धीमी हुई।

कांग्रेस ने इस मामले की गहराई से जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग की है। डोटासरा ने कहा कि अगर विपक्षी नेताओं को मामूली आरोपों पर जेल भेजा जा सकता है, तो प्रधानमंत्री के करीबी सहयोगी पर 2 हजार करोड़ रुपये के गंभीर आरोपों के बावजूद कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधते हुए पूछा, ₹क्या अडानी को कानून से ऊपर रखा गया है? क्यों सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है, जबकि इतने बड़े आर्थिक घोटालों पर चुप्पी साधी जा रही है?₹ इस बयान के जरिए कांग्रेस ने अपने अभियान ₹हम अडानी के हैं कौन₹ को और मजबूत करते हुए सरकार की जवाबदेही पर जोर दिया।

ठिठुरन बढ़ी, आबू सबसे ठंडा, तीन डिग्री लुढ़का पारा

जयपुर । पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद बीते 4 दिनों में राजस्थान में मौसम तेजी से बदला है। प्रदेश में दिन और रात के तापमान में फर्क काफी बढ़ गया है। कई शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है। हिल स्टेशन माउंट आबू बीते 24 घंटों में प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा है। यहां न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री दर्ज किया गया है। सीकर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, सिरोही, उदयपुर और चित्तोड़गढ़ में भी न्यूनतम तापमान तेजी से लुढ़ रहा है। हनुमानगढ़ और गंगानगर में दिन के वक्त घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो बाड़मेर गर्म इलाका रहा। यहां अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान की बात करें तो हिल स्टेशन आबू पर न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री रहा। सीकर का न्यूनतम तापतान 7.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहा।

फतेहपुर में अधिकतम तापमान 26.5 और न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रहा। गंगानगर व हनुमानगढ़ में न्यूनतम तापामन के मुकाबले मौसम में ज्यादा ठंडक महसूस की जा रही है। गंगानगर में अधिकतम तापमान 30 व न्यूनतम 10 डिग्री दर्ज किया गया। चूरू में अधिकतम तापमान 27.3 व न्यूनतम 9.9 डिग्री रहा। अजमेर में बीते 24 घंटों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री और लुढक गया है । यहां न्यूनतम तापमान न्यूनतम पारा 10.7 डिग्री से फिसलकर 8 डिग्री हो गया है। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां न्यूनतम 13.6 से लुढ़कर 10.6 डिग्री हो गया है। पिछले 24 घंटों में तुलना करें तो यहां न्यूनतम तापमान में लगभग 3 डिग्री की कमी आई है।

शुद्ध आबोहवा के लिए हिमाचल का रुख कर रहे सैलानी

शिमला । दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने से बड़ी संख्या में सैलानियों ने हिमाचल के पर्यटन स्थलों का रुख करना शुरू कर दिया है। वीकेंड पर प्रदेश के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हो गए हैं। दिल्ली के दफ्तरों में वर्कफ्रॉम होम शुरू होने के बाद कई सैलानियों ने होम स्टे के लिए संपर्क कर लंबे समय के लिए कमरों की बुकिंग को लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वीकेंड पर शिमला, मनाली, कुल्लू और धर्मशाला में सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। शिमला में 60 से 70, मनाली में 40 से 60 और धर्मशाला में 40 फीसदी तक ऑक्यूपेंसी पहुंच गई है। शनिवार को लाहौल-स्पीति की चंद्राघाटी और कोकसर में हुई ताजा बर्फबारी के बाद सैलानियों की संख्या और अधिक बढ़ने की संभावना है।

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद दिल्ली के स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। इसके बाद हिमाचल में फैमिली ट्रिप पर आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ गई है। शुक्रवार को ही शिमला में सैलानियों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। शनिवार को शहर की पार्किंगों में पर्यटक वाहनों के अलावा बाहरी राज्यों के टेंपो ट्रैवलर पार्क रहे। शहर के अंदर सबसे बड़ी लिफ्ट कार पार्किंग दोपहर एक बजे पैक हो गई और संचालकों ने एंट्री प्वाइंट पर पार्किंग फुल का बोर्ड लगा दिया। रिज मैदान और मालरोड पर पूरे दिन सैलानियों की खूब चहलपहल रही। धर्मशाला के होटलों में ऑक्यूपेंसी सामान्य दिनों में जहां 20 से

25 फीसदी चल रही है, वीकेंड पर 40 फीसदी तक पहुंच रही है।

होटल एसोसिएशन धर्मशाला के अध्यक्ष अश्विनी बांबा ने बताया कि मैदानी इलाकों में स्मॉग से राहत के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों के कर्मचारी वर्कफ्रॉम होम के लिए धर्मशाला के होम स्टे में पहुंचने शुरू हो गए हैं। कुल्लू के पर्यटन स्थल मनाली, मणिकर्ण, तीर्थन वैली, बंजार के जिभी और सोझा में सैलानियों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। होटलों की आक्यूपेंसी 40 से 60 फीसदी तक पहुंच गई है। सोलंग नाला में पर्यटक पैराग्लाइडिंग, ब्यास में रिवर राफ्टिंग और हॉट बैलून का आनंद ले रहे हैं। चंबा के डलहौजी और खज्जियार में भी पर्यटकों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है।

स्कूल का खेल मैदान बना डाला पार्किंग का अड्डा

तेलका (चंबा)। उच्च न्यायालय शिमला के विद्यालयों के खेल मैदान में स-ार्वजनिक गतिविधियों की बंदिश के आदेशों को तेलका विद्यालय में ठेंगा दिखाया जा रहा है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तेलका का खेल मैदान इन दिनों पार्किंग स्टैंड बनता ही नजर आ रहा है। विद्यालय के गेट को शरारती तत्वों की ओर से तोड़ा जाना, इसकी मुख्य वजह है। खेल मैदान का गेट टूटा होने की सूरत में यहां पर लोग की ओर से अपने वाहनों को बेधड़क होकर पार्क किया जा रहा है।

दूसरी ओर स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी अंगुली उठती नजर आ रही है। हालांकि, स्कूल प्रबंधन अब पुलिस विभाग को शरारती तत्वों पर शिकंजा कसने और वाहनों को खेल मैदान से खदेड़ने संबंधी सूचना देने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। तेलका वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में वर्तमान समय में 428 विद्यार्थी शिक्षा हासिल करने के लिए पहुंचते हैं। यहां के मैदान में पार्किंग होने से विद्यार्थियों की खेल प्रतिभाएं भी दबकर रह सकती हैं।

अभिभावक संजीव कुमार, पवन कुमार, सुरेश कुमार, संजय कुमार, मान सिंह, बचन सिंह, दलीप कुमार और प्रवीण कुमार ने बताया कि तेलका विद्यालय में 428 विद्यार्थी ग्राम पंचायत तेलका, सालवां, मोड़ा, दरेकड़ी, बाड़का, भजोतरा, सेरी से वाहनों और पैदल चल कर पांच से 12 किलोमीटर तक का सफर तय कर पढ़ने के लिए पहुंचते हैं। बावजूद इसके स्कूल में चहारदीवारी के मुख्य गेट तोड़ कर खेल मैदान को वाहन चालकों ने पार्किंग स्थल बना दिया गया है। स्कूल प्रबंधन को इस बारे सख्त कदम उठाने चाहिए।

एसएमसी अध्यक्ष चमारू राम ने बताया कि जल्द ही एसएमसी की बैठक आयोजित करवा कर इस बारे जरूरी निर्णय लेकर स्कूल गेट स्थापित करवाने के प्रयास रहेंगे। बताते चला जाए कि तेलका विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय शर्मा के अनुसार स्कूल गेट तोड़ने और वाहनों को पार्क करने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत पत्र सौंपा गया है। चौकी प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि उनके पास शुक्रवार को स्कूल का गेट तोड़ने और खेल मैदान में वाहनों को पार्क करने संबंधी एक शिकायत पत्र पहुंचा है। पुलिस विभाग शिकायत पत्र के आधार पर मामले की जांच करेगा।

पुरातत्व धरोहर एवं संग्रहालय में प्रदर्शित पुरावशेष पर आधारित कार्यक्रम संपन्न

भोपाल । अपनी धरोहर को करीब से जानने, उस-ाको निहारने और उसके लिए समग्र जानकारी जुटाने के लिए एक बहु आयामी आयोजन किया जा रहा है। विश्व धरोहर सप्ताह के शीर्षक से आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पुरातत्त्व, अभिलेखागार और संग्रहालय संचालनालय द्वारा विभिन्न विधाओं को उकेरा जा रहा है। 19 से 25 नवंबर तक मनाए जा रहे विश्व धरोहर सप्ताह के अंतर्गत बुधवार को एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता ₹पुरातत्व धरोहर एवं संग्रहालय में प्रदर्शित पुरावशेष पर आधारित₹ थी। प्रतियोगिता दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक आयोजित की गई और

इसमें प्रदेशभर के 100 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का सबसे अनोखा पहलू यह था कि विद्यार्थियों को संग्रहालय में रखी मूर्तियों के सामने बैठकर प्रेरणा लेने का अवसर मिला, ताकि वे पुरातत्विक धरोहर से जुड़े अपनी कलात्मक रचनाएं प्रस्तुत कर सकें। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं को हमारे सांस्कृतिक धरोहर और पहचान को समझने के लिए प्रेरित करना था, ताकि वे अपने इतिहास और संस्कृति के महत्व को जानें और उसे संजोकर रखें। यह आयोजन विद्यार्थियों के बीच पुरातत्व धरोहर के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। चित्रकला प्रतियोगिता के परिणाम विश्व धरोहर सप्ताह के अंतिम दिन 25 नवम्बर को घोषित किए जाएंगे।

वोटरों को लुभाने के लिए टूटती नैतिकता की मर्यादाएं

जिहाद इस्लामी संस्कृति का प्रचलित शब्द था है, लेकिन इसे भाजपा ने पहले प्रेम दिवारों के संदर्भ में 'लव जिहाद' बनाया और अब इसका इस्तेमाल सियासत में 'बोट जिहाद' के रूप में किया जा रहा है। ये दोनों नारे हालांकि है अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ किन्तु अब इनका इस्तेमाल सभी लोग कर रहे है। चुनाव को किसी धर्मयुद्ध की तरह लड़ने के लिए सारी बिसातें भाजपा की बिछाई हुई है। इन चुनावों में न स्थानीय मुद्दे हैं और न प्रचार अभियान में स्थानीय नेता चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने प्रदेशी नेताओं की फौज उतार दी है जो ध्रुवीकरण के लिए अपनी सारी प्रतिभा और क्षमता का इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। पिछले महीने हरियाणा और जम्मू-काश्मीर के चुनाव नतीजों के बाद अचानक से महाराष्ट्र और झारखण्ड के चुनाव महत्वपूर्ण बन गए, या कहिये बना दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के अलावा मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का इस्तेमाल दोनों राज्यों में झूठ परोसने, मतदाताओं के बीच उत्तेजना पैदा करने के लिए किया गया। विपक्ष की और से ले-देकर राहुल गांधी तथा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही चुनाव प्रचार में मोर्चा लेते दिखाई दिए। इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता या तो इन दोनों राज्यों के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं किये गए और न वे आये। इन दोनों राज्यों को जीतने से केंद्र की वैशाखियों पर टिकी भाजपा गठबंधन की सरकार की ताकत में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो सकती है। यदि 23 नवम्बर को चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में आये तो भाजपा को 25 नवम्बर से शुरू से रहे संसद के शीत सत्र में लंबित विधेयकों को पारित करने में आसानी हो सकती है और यदि भाजपा ने ये चुनाव न जीते तो उसकी मुसीबतें संसद और संसद के बाहर बढ़ सकती है। इन दो राज्यों के चुनाव में यदि विपक्ष जीतता है तो विपक्ष को एक नयी संजीवनी मिल सकती है। महाराष्ट्र और झारखण्ड के चुनाव सता और विपक्ष के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र और झारखण्ड विधानसभा के चुनावों को लेकर पहली बार आम आदमी पार्टी परिदृश्य से बाहर दिखाई दे रही है किन्तु औबेदु औवेसी मैदान में मौजूद हैं। वे अपनी पार्टी के फायदे के लिए मौजूद है या भाजपा की मदद के लिए ये कहना कठिन है। इस चुनाव में बटने और न घंटने के संपर्क है जो एक रहेगा, यो फरहेगा जो घटेगा वो कटेगा। कल की रात में दोनों पक्षों की ओर से वोट जिहाद के लिए जी-तोड़ परिश्रम किया जा रहा है आयोग भी इन चुनावों में बहुत सक्रियता दिखाई है। सभी दलों के नेताओं के उड़नखटोलों के साथ ही वाहनों की भी जमकर जांच की है। इन दो राज्यों के विधानसभा चुनाव इसलिए भी याद किये जायेंगे क्योंकि इन चुनावों में मुद्दों से ज्यादा मुर्दे काम आये है। काले खां घाटे में रहे लेकिन बिरसा मुंडा को फायदा हो गया।

दोनों राज्यों के मतदाताओं, प्रत्याशियों को आतंकित करने के लिए जब नारे काम न आये तो ईडी यानि प्रवर्तन निदेशालय तक ने खुलकर ने भाजपा के लिए काम किया। भाजपा के लिए दुर्भाग्य ये रहा कि चुनाव के अंतिम चरण में जा एक बार फिर मणिपुर धधका वहीं प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार छोड़कर नाइजीरिया और ब्रिक्स की बैठक में शामिल होने के लिए जाना पड़ा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को मणिपुर की हिंसा ने मैदान छोड़ने के लिए विवश कर दिया लेकिन योगी, सरमा और चौहान मोर्चे पर डटे हुए हैं। भाजपा ने लगता है कि इन दोनों राज्यों को जीतने के लिए हरियाणा की तरह इंतजाम कर लिया है। लेकिन मशीन और मशीनरी पर कितना भरोसा किया जा सकता है। कभी-कभी नेता ही नहीं मशीने भी बगावत कर जाती है।

▶ युवा भारतीय महिलाओं की उभरती आकांक्षाएँ

पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं और मानदंडों को चुनौती देती महिलाएं

उच्च शिक्षा और कौशल विकास में लड़कियों की अब लड़कों के बराबर शैक्षिक उपलब्धि है, जिसमें 50% से अधिक युवा महिलाएँ कक्षा 12 पूरी कर रही हैं और 26% कॉलेज की डिग्री प्राप्त कर रही हैं। युवा महिलाएँ विभिन्न कैरियर पथों और डिजिटल कौशल प्लेटफॉर्म तक पहुँच से प्रभावित होकर पेशेवर महत्त्वाकांक्षाओं को तेजी से प्राथमिकता दे रही हैं। स्किल इंडिया मिशन और स्टेम फॉर गर्ल्स इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने तकनीकी क्षेत्रों में युवा महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया है।

पिछले एक दशक में युवा भारतीय महिलाओं की आकांक्षाओं में एक परिवर्तनकारी बदलाव देखा गया है, जो उनकी बढ़ती स्वायत्तता, शिक्षा और कार्यबल में भागीदारी को दशार्ता है। यह विकास भारत के सामाजिक परिदृश्य को महत्त्वपूर्ण रूप से पुनर्परिभाषित कर रहा है।

उच्च शिक्षा और कौशल विकास में लड़कियों की अब लड़कों के बराबर शैक्षिक उपलब्धि है, जिसमें 50% से अधिक युवा महिलाएँ कक्षा 12 पूरी कर रही हैं और 26% कॉलेज की डिग्री प्राप्त कर रही हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (2017-18) उच्च शिक्षा में महिलाओं के बढ़ते नामांकन पर प्रकाश डालता है, जिसमें महिला सकल नामांकन अनुपात 27.3% तक पहुँच गया है। युवा महिलाएँ विभिन्न कैरियर पथों और डिजिटल कौशल प्लेटफॉर्म तक पहुँच से प्रभावित होकर पेशेवर महत्त्वाकांक्षाओं को तेजी से प्राथमिकता दे रही हैं। स्किल इंडिया मिशन और स्टेम फॉर गर्ल्स इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने तकनीकी क्षेत्रों में युवा महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया है।

विवाह की औसत आयु 2005 में 18.3 वर्ष से बढ़कर 2021 में 22 वर्ष हो गई है, जिसमें अधिक युवा महिलाएँ अनुकूलता के आधार पर साथी चुनती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 52% महिलाओं ने साथी चयन में अपनी बात रखी, जो 2012 में 42% थी। कई युवा महिलाएँ आर्थिक स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रही हैं, विशेष रूप से उद्यमिता के माध्यम से, क्योंकि सरकार महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए समर्थन दे रही है। उदाहरण के लिएः नीति आयोग द्वारा महिला उद्यमिता मंच ने 10, 000 से अधिक महिला उद्यमियों के नेटवर्क को बढ़ावा दिया है। युवा महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय शासन में बढ़ती भागीदारी के साथ राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय हैं। ग्रामीण महिलाओं के बीच स्वयं सहायता समूह सदस्यता 2012 में 10% से बढ़कर 2022 में 18% हो गई। ये आकांक्षाएँ पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं और मानदंडों को चुनौती दे रही हैं। जैसे-जैसे अधिक महिलाएँ करियर बना रही हैं, घरों में पारंपरिक लैंगिक अपेक्षाएँ बदल रही हैं। मनरेगा पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन प्रदान करता है, जो ग्रामीण घरेलू गतिशीलता को प्रभावित करता है। अधिक शिक्षा और आय के साथ, युवा महिलाओं का अब परिवार के वित्तीय और सामाजिक निर्णयों में अधिक प्रभाव है। स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीण महिलाओं को सामूहिक रूप से घरेलू वित्त का प्रबंधन करने के लिए सशक्त बनाया है। बाद में विवाह करने और साथी चुनने में सक्रिय भागीदारी की ओर बदलाव ने अरेंज मैरिज की पारंपरिक संरचना को चुनौती दी है। बाल विवाह में कमी और बाद में विवाह करने को प्राथमिकता देने की रिपोर्ट करता है। बढ़ती स्वतंत्रता ने सामाजिक प्रतिबंधों को चुनौती देते हुए शिक्षा या काम के लिए महिलाओं की अकेले यात्रा को सामान्य बना दिया है। 2012 में 42% की तुलना में अब 54% महिलाएँ बस या ट्रेन से अकेले यात्रा करने में सहज महसूस करती हैं। युवा महिलाएँ पेशेवर सेटिंग्स में लैंगिक समानता के बारे में तेजी से मुखर हो रही हैं, कानूनी और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दे रही हैं। पोष अधिनियम (कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम), 2013 ने महिलाओं को कार्यस्थल के मुद्दों को प्रभावी ढंग से सम्बोधित करने के लिए सशक्त बनाया है। स्वयं सहायता समूह और ग्राम सभाओं में युवा महिलाएँ शासन में महिलाओं की भूमिका पर पारंपरिक विचारों को चुनौती दे रही हैं। केरल कुदुम्बश्री मिशन महिला-नेतृत्व वाले शासन को बढ़ावा देता है, जिसने राज्यों में इसी तरह के मॉडल को प्रेरित किया है।

भारतीय महिलाएँ ऊर्जा से लबरेज, दूरदर्शिता, जीवन्त उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर के शब्दों में, हमारे लिए महिलाएँ न केवल घर की रोशनी हैं, बल्कि इस रौशनी की लौ भी हैं। अनादि काल से ही महिलाएँ मानवता की प्रेरणा का स्रोत रही हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले तक, महिलाओं ने बड़े पैमाने पर समाज में बदलाव के बडे.उदाहरण स्थापित किए हैं। 2030 तक पृथ्वी को मानवता के लिए स्वर्ग समान जगह बनाने के लिए भारत सतत विकास लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ चला है। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण करना सतत विकास लक्ष्यों में एक प्रमुखता है। वर्तमान में प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, समावेशी आर्थिक और सामाजिक विकास जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है।

महिलाओं में जन्मजात नेतृत्व गुण समाज के लिए संपत्ति हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी धार्मिक नेता ब्रिघम यंग ने ठीक ही कहा है कि जब आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं, तो आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं। जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं।

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से महिलाएँ न केवल खुद को सशक्त बना रही हैं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था की मजबुती में को भी योगदान दे रही है। सरकार के निरन्तर लगातार आर्थिक सहयोग से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में उनकी भागीदारी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 6-7 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों का अभियान और तेज हुआ है। आज देश भर में 70 लाख स्वयं सहायता समूह हैं। महिलाओं के पराक्रम को समझने की जरूरत है, जो हमें महिमा की अधिक ऊंचाइयों तक पहुँचाएगी। आइए हम उन्हें आगे बढ़ने और फलने-फूलने में मदद करें। महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण के लिए 'अमृत काल' इन्हें समर्पित हो। युवा भारतीय महिलाओं की उभरती आकांक्षाएँ भारत के सामाजिक ताने-बाने को उत्तरोत्तर रूप से परिभाषित कर रही हैं, एक ऐसे समाज को बढ़ावा दे रही हैं जहाँ लैंगिक समानता और महिलाओं की एजेंसी आदर्श बन गई है। सहायक नीतियों को सुनिश्चित करने से इस बदलाव में तेजी आ सकती है, जिससे समावेशी और सशक्त भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

-प्रियंका सौरभ

तकनीक के दुरुपयोग सजा निर्धारित हो

कैमरा और ड्रोन जैसी तकनीके न सिर्फ लड़कियों और महिलाओं को जगह-जगह परेशानी हिंडेन कैमरा लगाकर इनके फोटो निकालते है यहीं ग्रामीण क्षेत्र में जंगल के इलाके भी भी जहां महिलाएं अपनी निजता के तहत अपनी खुशी मना सकती थीं वहां भी इन तकनीकों ने आफत मचा दी है।

कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ता त्रिशांत सिमलाई ने 14 महीनों तक उत्तर भारत के कॉट टाइगर रिजर्व के पास 270 लोगों से बात की। उन्होंने पाया कि ये कैमरा ट्रैप और ड्रोन सनी महिलाओं की आजादी पर गहरा असर बल रही है। इसका प्रयोग महिलाओं की निगरानी के लिए भी होने लगा है। एक शोध में दावा किया गया है कि भारत में वन्यजीवों जैसे बाघों की निगरानी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कैमरा ट्रैप और ड्रोन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल ग्रामीण महिलाओं को परेशान करने और उनकी जासूसी करने के लिए हो रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास रहने वाली महिलाओं के लिए जंगल एक ऐसा स्थान है जहां वे पारंपरिक और पितृसतात्मक समाज से दूर अपनी आजादी महसूस करती थीं. वे वहां गोत गातों वर्जित विषयों पर चर्चा करती और कभी-कभी धूम्रपान और शराब का सेवन भी करती थी। लेकिन अब जंगलों में लगे कैमरा ट्रैप और ब्रेन ने महिलाओं की आजादी और निजता में सेंध लगा दी है। सिमलाई ने कहा, 'इन तकनीकों ने पुरुष प्रधान समाज की निगाहों को जंगल तक बढ़ा दिया है। एक वन अधिकारी ने शोधकताओं को बताया कि जब एक कैमरा ट्रैप ने जंगल में एक जोड़े की रोमांस करते हुए तस्वीर ली, तो हमने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दी। 2017 में एक कैमरा ट्रैप ने एक ऑटिस्टिक महिला की तस्वीर खींच लो, जब वह जंगल में शौच कर रही थी। इस तस्वीर को अस्थायी वन कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। इससे नाराज ग्रामीणों ने कैमरा ट्रैप तोड़ डाले. त्रिशांत सिमलाई ने बताया कि अस्थायी वन कर्मियों के रूप में नियुक्त युवकों ने इस फोटो को स्थानीय एप और फेसबुक ग्रुप पर साझा किया ताकि महिला को शर्मिंदा किया जा सके। एक स्थानीय निवासी ने शोधकताओं से कहा, जब हमारे गांव की बेटी को इस तरह बेशर्मी से अपमानित किया गया, तो हमने हर कैमरा ट्रैप को तोड़ दिया और जला दिया। एक स्थानीय महिला ने शोध में बताया, हम कैमरों के सामने नहीं चल सकते या ऐसे बैठ नहीं सकते, जिससे हमारी तस्वीर गलत तरीके से खींची जा सके।

सिलाई ने अपने शोध में कहा है कि ड्रोन का भी महिलाओं को डराने के लिए दुरुपयोग किया गया। कई बार ड्रोन महिलाओं के ऊपर उड़ाए गए, जिससे वे डरकर अपने काम को छेड़कर भाग गई। महिलाओं ने कैमरों से बचने के लिए जंगल के गहरे हिस्सों में जाना शुरू किया है, जो खात्रों के लिए जाना जाता है। इस बदलाव के चलते एक महिला इस साल बाग के हमले में मारी गई। इस महिला ने 2019 में इन कैमरों को लेकर चिंता जाहिर की थी। वहीं, कुछ महिलाओं ने इन तकनीकों का फायदा भी मिला है। शोध के अनुसार एक महिला ने बताया कि जब उसका पति उसे पीटता था, तो यह कैमरे के सामने भाग जाती थी ताकि उसका पति उसका पीछा न करे। सिमलाई ने कहा कि ये तकनीकें वन्यजीव संरक्षण के लिए बहुत प्रभावी हैं, लेकिन इनका उपयोग स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श करके और अधिक पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने यन अधिकारियों को स्थानीय कर्मचारियों को संवेदनशील प्रशिक्षण देने की सलाह दी।

शेफील्ड यूनिवर्सिटी की संरक्षण विशेषज्ञ रोसलीन डफी ने कहा, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि ये तकनीकें महिलाओं को परेशान करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। मुझे हैरानी इस बात पर है कि यह कल्पना करते हैं कि तकनीकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शून्य में पेश और इस्तेमाल किया जा सकता है। डफी ने कहा, इस शोध में जो मामले हैं, वे संयोग नहीं हैं। ये सक्रिय रूप से ड्रोन का इस्तेमाल महिलाओं को परेशान करने के नए तरीके देने के लिए कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि तकनीक के उपयोग के लिए स्पष्ट नियम और दुरुपयोग के लिए कड़ी सजा होनी चाहिए।

नतीजे स्पष्ट करते हैं कि ....

शायद सबसे अधिक चौंकाने वाला निष्कर्ष राजनीति के सबसे बुजुर्ग नेता शरद पवार की चमक का फीका पड़ना है। उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल से चार दशकों तक राज्य की राजनीति पर प्रभुत्व जमाकर रखा, जिसके दम पर उन्होंने अनेक सरकारें बनाईं, और गिराईं। लेकिन इस बार वह पूरी तरह विफल हो गए और अपने गढ़ पश्चिमी महाराष्ट्र को नहीं बचा पाए। इस क्षेत्र में उनके भतीजे अजीत पवार के गुट ने राकांपा बनाम राकांपा की लड़ाइ में सर्वाधिक सीटें अर्जित करने में सफलता प्राप्त की। शरद पवार ने खुद यह घोषणा की थी कि उनका यह अंतिम चुनाव है। इस दिग्गज के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 84 साल की उम्र में और कमजोर स्वास्थ्य के बावजूद वह अपने लिए राजनीति से एक सम्मानजनक विदाई की पटकथा लिखने में विफल रहे।

हालांकि झारखंड में मिली जीत इंडिया गठबंधन के लिए एक आशा की किरण है। कांग्रेस इसका सही उपयोग भाजपा को जवाब देने के लिए कर सकती है, लेकिन नतीजे स्पष्ट करते हैं कि इस जीत का पूरा श्रेय हेतुत सोरेन और उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा को जाता है। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के बाद सहानुभूति की लहर और आदिवासी वोटों के एकीकरण के दम पर अपने लिए दूसरा कार्यकाल जीतने के लिए कांग्रेस का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया था। सोरेन के अभियान का मुख्य मुद्दा आदिवासी पहचान का संरक्षण और आदिवासियों को सरना कोड के लिए सांविधानिक दर्जा रहा जो भाजपा के बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर भारी पड़ता दिखा। चूंकि सांविधानिक आवश्यकताओं के अनुसार, महाराष्ट्र में अगली सरकार 26 नवंबर तक बननी है, इसलिए महायुति इस जटिल प्रश्न को निपटाने के लिए तेजी से कदम उठाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी अब वायनाड लोकसभा उपचुनाव जीतने वाली बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के रूप में अपने शस्त्रागार में एक अतिरिक्त तीर से जरुर युक्त हुए हैं। उम्मीद है कि वह उद्योगपति गौतम अडाणी के खिलाफ जारी अमेरिकी गिरफ्तारी वारंट को लेकर मोदी सरकार पर अपने सभी शस्त्र चलाएंगे, लेकिन उनकी पार्टी का हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद से जिस तरह का प्रदर्शन रहा है वह उनकी धार को कुंद ही करेगा। फिलहाल यह तय नहीं है कि प्रमुख व्यवसायी पर हमला करने के लिए राहुल गांधी को इंडिया गइबंधन के ही उनके साझेदारों से कितना समर्थन मिलेगा, क्योंकि अडाणी का न केवल कई राज्यों में भारी निवेश है बल्कि मोदी सरकार के साथ भी उनके करीबी संबंध हैं। महाराष्ट्र में मिली प्रचंउ जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए गेमचेंजर साबित होगी, जिसकी उसे लोकसभा चुनाव में सम्पूर्ण बहुमत न मिलने के बाद से तलाश थी।

प्रथमदृष्टया, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के नतीजों का स्कोर कार्ड बराबरी पर रहा है। भाजपा की अगुवाई वाले महायुति ने महाराष्ट्र में सूपड़ा साफ किया है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस वाला इंडिया गठबंधन झारखंड में अपनी सत्ता बरकरार रखने में सफल रहा। हालांकि महाराष्ट्र में भाजपा द्वारा संचालित महायुति की जीत की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है, क्योंकि इसका असर निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा। राजनीतिक दूष्टि से उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, जिसमें 48 लोकसभा सीटें हैं।

घूँघट की बगावत

24 नवम्बर 2024

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

4

शांति के राजनीति समाधानों की आवश्यकता

मणिपुर हिंसा से मुक्त नहीं हो पा रहा। हिंसा लगातार जारी है। हां, उसकी मात्रा घटती-बढ़ती रही है। ताजा हिंसा के स्रोतों का अध्ययन किया जाये तो कुद दिन पूर्व छह मैतेई लोगों की हत्या को अंजाम तक पहुंचाया गया इसकी प्रतिक्रिया में कुकी जनजाति के गांवों पर हमले किए गए। अब आक्रोश का गुबार इस तरह से फूटा कि विधायकों, मंत्रियों के घर पर हमले होने लगे हैं। मुख्यमंत्री के पुश्तैनी मकान तक पर हमला किया गया। माह नवंबर में हिंसा की पुनरावृत्ति अधिक हुई है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि यहां पहाड़ों और घाटियों के बीच संवाद का पूर्णतया अभाव देखा गया। न संवाद की कोशिश न तो सरकार की ओर से इस दिशा में कोई प्रयास ही देखने को मिले साथ ही साथ सोसाइटी के लिए जगह भी नहीं है। यह बात शुरू से ही उठाई जाती रही है कि सिविल सोसायटी के दोनों पक्षों की ओर से थोड़ी जगह मिलनी चाहिए ताकि समाधान के लिए बात आगे बढाई जा सके।

ऐसे में एक खतरा यह है कि अगर विद्रोही या उग्रवादी स्तर पर बात होती है तो चुनौतियां बहुत बढ़ सकती हैं। मणिपुर की वास्तविकता यह है कि वहां जब संवाद की स्थितियां नहीं है तो शांति की उम्मीद कै से और किस प्रकार से की जा सकती है। इसकी चर्चा अब लोगों के बीच में अक्सर की जाती रही है।

मणिपुर में नेशनल पीपुल्स पार्टी के सदस्यों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। यह अलग बात हैकि वहां की सरकार को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। 60 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के मुख्यमंत्री वीरेन्द्र सिंह के पास 37 विधायकों का समर्थन उपलब्ध है। मणिपुर में अब अधिकांशतः यह स्वीकार करने लगे हैं कि मुख्यमंत्री शांति बहाल करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। केन्द्रीय स्तर से भी कदमों का अभाव देखने को मिल रहा है। मणिपुर में ऐसे नए और सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता महसूस हो रही है जो समाधान का मार्ग प्रशस्त करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करे।

वर्तमान में जो हालात हैं उसमें संपूर्ण विभाजन की स्थिति बन जाएगी। पहाड़ और मैदान के बीच विभाजन नहीं होना चाहिए। यह भी ध्यान देना होगा कि पहाड़ पर या मैदान में एक ही तरह के लोग नहीं रहते हैं। नेताओं को ज्यादा संवेदनशीलता के साथ विचारना होगा। अभी, हाल में मिजोरम के मुख्यमंत्री ने अमेरिका में जाकर एक गलत बयान दिया है, उसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। मणिपुर के विवाद को मिजोरम से किस आधार पर हवा मिल रही है? कूकियों का जुड़ा मिजो जनजाति से है और बड़ी संख्या में कुकी जनजाति के लोग म्यांमार से भी मणिपुर यामिजोरम आकर बसे हैं। कुकियों के साथ हथियार भी भारत आए हैं इसे कोई भी नकार नहीं सकता। मणिपुर में जो हुआ है उसे लेकर मिजोरम में भी आक्रोश देखा गया। अतः सरकारों को अधिक गंभीर होकर राजनीतिक कटुता को रोकना होगा। सावधान रहना होगा कि एक चिन्गारी भी आग लगाने के लिएपर्याप्त होती है। पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों को अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है ताकि कटुता को शीघ्र अति शीघ्र समाप्त किया जा सके। कटुता भरे बयानों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे बयान अक्सर आएंगे तो अलग-अलग समुदाय के लोगों को संवाद के लिए तैयार करना आसान नहीं होगा। समाधान का पहला रास्ता राजनीतिक संवाद को आगे बढ़ाना माना गया है। दूसरा रास्ता थोड़ा बल प्रयोग पर बल प्रयोग भी उसी मात्रा में किया जाए जितने की आवश्यकता है। और हिंसा की आग शांत हो सके।

लोगों के साथ हो रही हिंसा को हर हाल में रोकना चाहिए। मणिपुर में कोईशत्रु नहीं है। सब अपने लोग हैं, उन्हें अमन-चैन की ओर लाने के लिए राजनीतिक समाधान तलाशना होगा। शांति पहला लक्ष्य है पर अंतिम समाधान राजनीतिक ही होगा।

अब तो ऐसा लगने लगा है कि केवल संवाद की राह खोजने से समाधान नहीं निकलेगा या हिंसा नहीं रुकेगी। अब राजनीतिक समाधान खोजना पड़ेगा। हमने पहले भी देखा है राजनीतिक सहमति के बिना समाधान खोजा गया, तो शांति भंग व हिंसा की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं।

मणिपुर में विभिन्न समूहों की जो मांगें हैं उन पर राजनीतिक स्तर पर ध्यान देना पड़ेा। आरक्षण, विकास और ज्यादा स्वायत्तता देने के विषय में विचारना होगा। पूर्वोत्तर में राजनीतिक स्वायत्तता देने के फायदे अनेक जगहों पर देखे गए हैं। ऐसे में अनेक इलाकों में हालात पहले से बेहतर हुए हैं। जो आदिवासी पहले उपेक्षा महसूस करते थे, उन्हें मुख्य धारा के साथ जोड़ने में काफी मदद मिली है। अतः एकजुट मणिपुर राज्य के हित में है कि यहां शांति के राजनीति उपाय किए जाएं।

स्मॉग पॉल्यूशन : एक लाइलाज प्रदूषण

उत्तर भारत का एक बड़ा क्षेत्र इन दिनो स्मॉग यानी जहरीले धुयें युक्त कोहरे जिसे धूम कोहरा भी कहा जाता है, की चपेट में है। यह कोई पहला अवसर नहीं है जबकि ह्यस्मॉग ह्य यानी जहरीले धुयें की खबरें मीडिया में सुर्खियां बटोर रही हों। बल्कि लगभग दो दशक से यह स्थित प्रत्येक वर्ष पैदा हो रही है। हाँ इतना जरूर है कि प्रदूषण दिन प्रतिदिन और भी न केवल बढ़ता जा रहा है बल्कि और भी जहरीला भी होता जा रहा है। इसका घोर प्रदूषण युक्त वातावरण का खामियाजा हमें तरह तरह से भुगतना पड़ रहा है। कहीं विमानों की उड़ानें प्रभावित हो रही हैं तो कहीं ट्रेंस परिचालन में बाधा आने के चलते रेल गाड़ियां लेट हो रही हैं। गत दिनों खराब मौसम के कारण ही दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 15 विमानों का मार्ग बदला गया जबकि 100 से अधिक उड़ानों में देरी हुई। सड़कों पर दुर्घटनाओं में इजाफा होने लगा है। स्वास्थ्य कारणों से बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाते हैं तो अस्पतालों में सांस और दमा के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ तक कि एक स्वस्थ व्यक्ति भी ऐसे वातावरण में सांस लेने में दिक्कत महसूस करने लगता है। लोगों को खुजली हो रही है और आंखों में जलन व आँखों से पानी आने की शिकायतें आ रही हैं। मास्क लगाना या न लगाना दोनों ही स्थिति में लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी बढ़ते प्रदूषण की वजह से हालात गंभीर बने हुए हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान के लाहौर में स्मॉग यानी जहरीले धुएं की इतनी मोटी चादर बिछ गई जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देने लगी। अब खबर तो यहां तक है कि स्मॉग यानी जहरीले धुएं से पैदा होने वाले इस प्रदूषण को कम करने के लिए वहां लॉकडाउन लगाने तक की योजना बन रही है।

सवाल यह है कि गत लगभग 2 दशक से निरंतर प्रदूषित होते जा रहे इस जहरीले धुएं युक्त वातावरण और अनेक माध्यमों से इनसे होने वाले आर्थिक नुक्सान व स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के लिये जिम्मेदार कौन है। सर्दियों की शुरूआत में हमेशा टी वी व अखबारों में यह सुर्खियां बनती हैं कि प्रदूषण का स्तर क्या है। विशेषज्ञों के अनुसार स्वच्छ हवा वाले वातावरण के लिये 50 तक अदकहोना चाहिये। 50 से कम अदक(एयर क्वालिटी इंडेक्स) स्वास्थ्य के लिये ठीक रहता है। जबकि दिल्ली राजधानी क्षेत्र (एन सी आर) से लेकर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक का एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले दिनों 500 के करीब पहुँच गया। सरकार से लेकर जनता तक इस अति प्रदूषित वातावरण से निजात पाने के लिये केवल प्रकृति के भरोसे बैठी हुई है कि या तो बारिश हो तो इस जहरीली हवा से निजात मिले या फिर तेज हवा

इस वातावरण से निजात दिलाये। जबकि प्रदूषण से त्राहि त्राहि करती यही जनता या जनता द्वारा चुनी उसकी सरकार इस समस्या से निपटने का कोई भी कारगर उपाय ढूंढ नहीं पाती।

कभी स्कूल्स में छुट्टी कर,कभी निर्माण कार्य रूकवाकर तो कभी सम-विषम नंबर के अनुसार वाहन चलने का निर्देश देकर ऐसी समस्याओं से निजात के उपाय तलाशे जाते हैं। जबकि प्रदूषण फैलाने के जिम्मेदार वाहनों की संख्या प्रतिदिन लाखों की तादाद में बढ़ती जा रही है। उद्योगों से प्रदूषित धुआं निरंतर निकलता रहता है। पूरे देश की सड़कें धुल मिटटी से पटी पड़ी हैं। खेतों में फसलों के अवशेष बेरोकटोक जलाये जा रहे हैं। जगह जगह आम लोग कूड़े के ढेर में बेखौफ होकर आग लगाते हैं जिनमें रबड़, पॉलीथिन, प्लास्टिक आदि सब कुछ जलाया जाता है। इसी तरह आतिशबाजी चलाने के लिये चाहे अदालतें मना करें या सरकारें, कोई भी मानने को तैयार नहीं। बल्कि हर साल आतिशबाजी का चलन व इनकी खपत बढ़ती ही जा रही है। यदि आप दीपावली पर आतिशबाजी चलाने को लेकर ज्ञान देने लगे तो समझो आप को सनातन विरोधी होने का प्रमाण पत्र तो उसी क्षण मिल जायेगा। गुरु पर्व पर होने वाली आतिशबाजी पर सवाल उठाया तो दीपावली का सवाल खड़ा होगा। इसी तरह शब बरात हो या नया साल,रोज होने वाले शादी ब्याह कोई भी आयोजन आतिशबाजी से अछूता नहीं है। और जाहिर है ऐसी आतिशबाजीयों का एक ही परिणाम है, जहरीला धुआं,जान लेवा प्रदूषण,स्मॉग यानी जहरीले धुएं युक्त कोहरे की चादर और अंततः बदलता मौसम व ग्लोबल वार्मिंग। जिसतरह बारिश के दिनों में शहरों में समुचित जल निकासी का प्रबंध न होने के चलते शहरों व कस्बों में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है और इससे संबंधित खबरें लेख व परिचचाएं वर्षा ऋतू के दौरान पढ़ने सुनने को मिलती हैं। परन्तु बारिश खत्म होते ही जनता व सरकार सभी हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और अगले साल की बारिश व इससे होने वाली तबाही की प्रतीक्षा करने लगते हैं। ठीक उसी तरह हर साल दीपावली के बाद और सर्दियों के आगाज में हर वर्ष यही प्रदूषण व जहरीले धुएं की चर्चा सुर्खियों में आ जाती है। इस विषय को लेकर हमारे समाज की जागरूकता व समझ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि न तो कोई अतिशबाजियों से परहेज के लिए तैयार है न ही यह मानने के लिये तैयार है कि पराली या खेतों में फसलों के अवशेष जलने से प्रदूषण फैलता है। धनाढ्य या नव धनाढ्य लोग मात्र एक सवारी के साथ सड़कों पर कारें दौड़ाते फिरते हैं। सड़कों पर बे रोकटोक धुंआ करना तो गोया लोगों के मौलिक अधिकारों में शामिल हो गया है। यहाँ तक कि रोजाना कई जगह खुद नगर पालिका के कर्मचारी झाड़ू देने के बाद जगह जगह इकठ्ठा किये गये कूड़े के ढेर में अपने ही हाथों से माचिस लगा देते हैं। गोया पढ़ा लिखा हो या अनपढ़,गरीब हो या अमीर,वैश्विक स्तर पर प्रदूषण बढ़ने के लिये सभी जिम्मेदार हैं। इसलिये भले ही सतही उपाय कितने ही क्यों न कर लिये जाएँ परन्तु हकीकत तो यही है कि स्मॉग प्रदूषण अब एक लाईलाज संकट बन चुका है।

जनजातीय उत्थान के लिए मध्यप्रदेश सरकार के उल्लेखनीय कदम

जनजातीय गौरव दिवस पर यह अवश्य याद रखना चाहिए कि अभारतीय ताकतों ने अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के अंतर्गत जनजातीय समुदाय को भ्रमित करने के लिए 9 अगस्त को वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स डे को आदिवासी दिवस कहकर भारत में बढ़ावा दिया गया। मध्यप्रदेश वह राज्य है, जिसकी पहल पर देश को जनजातीय गौरव दिवस मिला है। यह बात तो हर कोई मानता है कि मध्यप्रदेश की सरकार ने जनजातीय नायकों का गौरव बढ़ाने के लिए उनसे जुड़े स्मारकों का आगे बढ़कर विकास किया है। राजा शंकरशाह और रघुनाथ शाह, रानी कमलापति, रानी दुर्गावती, टंट्या मामा और भीमा नायक से लेकर कई नायकों के योगदान से लोगों को परिचित कराने के उल्लेखनीय कार्य किए हैं। मंडला के मेडिकल कॉलेज का नाम बलिदानी हृदयशाह के नाम पर किया गया। वहीं, छिंडवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकरशाह विश्वविद्यालय किया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया। जबलपुर में 100 करोड़ की लागत से रानी दुर्गावती स्मारक को विकसित किया जा रहा है। जनजातीय गौरव को बढ़ाने के साथ ही जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए भी मध्यप्रदेश सरकार ने उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। विगत 20 वर्षों में जनजातीय योजनाओं का बजट 1000 प्रतिशत बढ़ा है। मध्यप्रदेश पहला राज्य है, जहाँ जनजातीय समुदाय के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए पेसा कानून को लागू किया गया है। जनजातीय समुदाय से आनेवाली पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में 15 नवंबर, 2022 को मध्यप्रदेश के 20 जिलों के 89 विकासखंडों को पेसा कानून की सौगात मिली। मध्यप्रदेश के बजट का अध्ययन करें तो ध्यान आएगा कि 2003-04 में जनजातीय कार्य विभाग का बजट 746.60 करोड़ रुपये था। जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए संचालित योजनाओं को बजट की कमी का सामना न करना पड़े, इसके लिए भाजपा सरकार ने सबसे पहला काम यही किया कि जनजातीय कार्य विभाग के बजट में लगातार बढ़ोतरी की। वर्ष 2003-04 के मुकाबले वर्ष 2023-24 में जनजातीय कार्य विभाग का बजट 1000 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 11,768 करोड़ रुपये का हो गया है। इस बजट का उपयोग जनजातीय वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, रोजगार एवं अन्य बुनियादी व्यवस्थाओं के साथ ही विकास कार्यों को गति देने में किया गया है। विद्यार्थियों को शिक्षा के समुचित अवसर एवं आर्थिक सहयोग के साथ ही सरकार की ओर से रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण भी दिलाया जा रहा है। कम्प्युटर कौशल सिखाने के साथ जनजातीय युवाओं को पुलिस और सेना में भर्ती का प्रशिक्षण देने का काम भी मध्यप्रदेश में किया जा रहा है। जनजातीय वर्गों के उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए आहार अनुदान योजना, सिकल सेल उन्मूलन मिशन, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार ग्राम, देवारण्य, अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति अधिनियम-2020, मिलेट मिशन, प्रधानमंत्री वन-धन योजना, आकांक्षा योजना, प्रतिभा योजना, आवास सहायता योजना, विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति, प्री एवं पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए कोचिंग एवं प्रोत्साहन तथा जनजातीय लोक कलाकृतियों एवं उत्पादों की जीआई टैगिंग जैसे कदम मध्यप्रदेश में उठाए गए हैं।

जनजातीय गौरव दिवस पर यह अवश्य याद रखना चाहिए कि अभारतीय ताकतों ने अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के अंतर्गत जनजातीय समुदाय को भ्रमित करने के लिए 9 अगस्त को वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स डे को आदिवासी दिवस कहकर भारत में बढ़ावा दिया गया, जबकि इस दिन का भारत और जनजातीय गौरव के साथ कोई संबंध नहीं है। वास्तव में यह तो दुःखद त्रासदी की शुरूआत का दिन है। ब्रिटिस सेना ने अमेरिका के मूल निवासियों का नरसंहार किया। बाद में, उसके अपराध बोध से मुक्त होने के लिए वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स डे के रूप में 9 अगस्त को चुना गया। यहाँ यह भी ध्यान रखें कि वैश्विक षड्यंत्र के अंतर्गत ही वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स डे का अनुवाद विश्व आदिवासी दिवस के रूप में किया गया है। वास्तविकता यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने अब तक इंडिजिनियस पीपल की स्पष्ट परिभाषा तक नहीं की है। यही कारण है कि जब 1989 में विश्व मजदूर संगठन द्वारा ह्यराइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपलह्न कन्वेन्शन क्रमांक-169 घोषित किया गया, तब उसे विश्व के 189 में से केवल 22 देशों ने ही स्वीकार किया। इसका मुख्य कारण इंडिजिनस पीपल शब्द की परिभाषा को स्पष्ट नहीं करना ही था।↓प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने भारत माता के महान बेटे बिरसा मुंडा की जयंती (15 नवंबर) को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मान्यता देकर प्रशंसनीय कार्य किया है। जनजाति वर्ग के इस बेटे ने भारत की सांस्कृतिक एवं भौगोलिक स्वतंत्रता के लिए महान संघर्ष किया और बलिदान दिया। अपनी धरती की रक्षा के लिए उन्होंने विदेशी ताकतों के साथ जिस ढंग से संघर्ष किया, उसके कारण समूचा जनजाति समाज उन्हें अपना भगवान मानने लगा। उन्हें धरती आबा कहा गया। भगवान बिरसा मुंडा न केवल भारतीय जनजाति समुदाय के प्रेरणास्रोत हैं बल्कि उनका व्यक्तित्व सबको गौरव की अनुभूति कराता है। इसलिए उनकी जयंती सही मायने में गौरव दिवस है। जिस प्रकार भगवान बिरसा मुंडा ने विदेशी ताकतों के षड्यंत्रों से भारत को बचाया, उसी प्रकार उनकी स्मृति में मनाया जानेवाला जनजातीय गौरव दिवस भी हमें वर्तमान में चल रही साजिशों से बचाएगा और भारत के स्व की स्थापना की प्रेरणा देगा।

गौधन आवारा पशु के रूप में पहचाने जा रहे

सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ-ऋग्वेद, उपनिषद एवं पुराणों में ऋषियों ने गौधन की महिमा को लिपिबद्ध करके दुनिया को गाय के समस्-गुणों से परिचित करवाया था। परन्तु ऋषियों मुनियों द्वारा गौधन के संदर्भ में लिखे ज्ञान तथा उपदेशों को भारत में तिलांजलि दी जा चुकी है। शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शंकर के साथ नंदी की पूजा भी होती है, जिन देशों में सुख-समृद्धि की कामना के लिए बलिवैश्वदेव यज्ञ के माध्यम से घर की प्रथम रोटी दिव्य गुणों की स्वामिनी गाय को खिलाई जाती है, वहां प्रत्येक घर आंगन की शोभा रही गोविंद की प्रिय गाय तथा भगवान शिव के प्रिय नंदी को बेसहारा होकर सड़कों पर दुर्दशा, तशद्दुद एवं तस्करी का शिकार होकर बूचड़खानों तक का सफर तय करना पड़ेगा, पूज्य रहे गौधन आवारा पशु के रूप में पहचाने जा रहे हैं। गोवंश को गो-तसकरों के वाले करके गौ-पालन से पल्ला झाड़ने वाले प्रयासों से पीछा छुड़ाने के प्रयास होंगे, शायद गोपाष्टमी, गोवत्स द्वादशी एवं गोवर्धन पूजो से पर्व मनाने वाले भारत में इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। प्रश्न यह है कि गोवंश की इस बेकदरी के आलम का जिम्मेवार कौन है? श्वेत क्रांति, कृत्रिम गर्भाधान, चारागाहों, में चरता विकास, मुफ्तखोरी की योजनाएं आपरेशन फ्लड की आंधी, रोजगार की जुस्तजू में गांवों से युवाओं का पलायन, आधुनकता की चकाचौंध में भौतिकतावादी जीवनशैली या गौपालन व्यवसाय को उपयोगी बनाने में सियासी निजाम की उदासीनता। ध्यातव्य रहे कि तराजू किसी चीज का भार बता सकता है, गुणवत्ता नहीं। यदि मां के बाद किसी दूध की महिमा एवं महत्व है तो वह केवल गाय का दूध है। इसीलिए अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में एक मात्र प्राणी गाय को गौमाता का दर्जा प्राप्त है। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को मनाया जाने वाला गोपाष्टमी गौधन को समर्पित है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु के आवें अवतार श्रीकृष्ण ने इस दिन गौचारण लीला प्रारम्भ की थी। चंद्रवंशी क्षत्रिय श्रीकृष्ण गोपाल बने। गोरक्षक के रूप में श्रीकृष्ण का नाम गोविंद पड़ा। गावों ममाग्रतः सन्तुगावी ने सन्तु पृष्ठतः गांवों में हृदय सन्तु गवा मध्ये वसाम्यहम् । गायें मेरे आगे, पीछे एवं हृदय में स्थित रहे, गायों के बीच ही में सदा निवास करुं। गउओं के संदर्भ में श्रीकृष्ण के इस प्रसंग का उल्लेख भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में हुआ है। धाम्रिक ग्रंथों में जमदग्नि भारद्वाज, वशिष्ठ, अस्मित तथा गौतम जैसे महान ऋषियों के आश्रमों में नंदा, सुभदा सुरभि सुशीला एवं बहुला जैसी गऊओं के उल्लेख किये गये हैं। स्वस्थ जीवन शैली के लिए गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न मायन रखता है। विदेशी नस्लों की तुलना में स्वदेशी नस्ल की गऊओं में दुग्ध उत्पादन क्षमता कुछ हद तक कम हो सकती हैं, परन्तु पौराणिक शास्त्रों एवं आयुर्वेदिक तथा वैज्ञानिक कसौटियों पर स्वदेशी गौधन का दूध श्रेष्ठ साबित हुआ है। विश्व की सबसे उम्दा स्वदेशी नस्ल की गऊएं भारत में ही पाई जाती हैं। लेकिन अधिक दुग्ध उत्पादन के लालच में विदेशी नस्ल के गोवंश को अहमियत देकर अपने स्वदेशी गौधन को नजर अंदाज कर दिया गया। उनका स्वरूप बिगाड़ा गया।

शर्मिन्दगी : पुलिस कौन सा दायित्व निभा रही

समाजवादी पार्टी के आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी मतदान की शिकायतें की और उनकी चाहत थी कि बुर्के को हटाकर उनकी जांच पुलिस करे। हर चुनाव में भाजपा मुस्लिम वोटरों से घबरा जाती है। वैसे तो यह महिला सम्मान की बात करती है लेकिन जब बुक का मामला सामने होता है तो वह चुनाव में इसे ध्रुवीकरण का मुद्दा बनाती है और इसे फर्जी वोट से जोड़ देती है। जबकि पीठासीन अधिकारी की टीम लोगों के कार्ड जांचती है और तब उन्हें वोट करने की अनुमति देती है इस प्रक्रिया में लगभग दो मिनट का समय लगता है और तीन लोगों के पास से मतदाता को गुजरना पड़ता है कौन किस प्रकार के कपड़े पहने यह तो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। हिन्दू समाज में औरतें पहले घूंघट करके बाहर निकलती थीं। यही नहीं वे घर में भी घूंघट में होती थीं। जैसे-जैसे समय बदलता गया। यह घूंघट काफी कम हो गया है। कुछ समाज में आज भी यह प्रचलित है। आज भी महिलाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि जब वे बाहर निकलें खासकर सार्वजनिक जगहों पर तो सिर पर पल्लू रखें। मुस्लिम समाज में बुर्का और हिजाब भी इसी प्रकार का पहनावा माना जा सकता है। ईरान में तो जिस प्रकार का विरोध इसके खिलाफ चल रहा है कि महिलाओं ने खुद ही इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है जिसके लिए उन्हें मॉरल पुलिस के दंड का शिकार होना पड़ रहा है। पुलिस का राजनीतिकरण इस पूरी व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। जिसका आरोप पिछले कई दशकों से उत्तर प्रदेश की पुलिस पर लगता रहा है। अब तो इस प्रक्रिया में आईएएस अधिकारी भी आ गए हैं जो अपने को बहुत श्रेष्ठ मानते आये हैं, जिन्हें कम से कम इससे अलग माना जाता था।

उत्तर प्रदेश में नौ सीटों पर होने वाले चुनाव हंगामे और पांच पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने के साथ सम्पन्न हो गए। कुल नौ सीटों के उपचुनाव में मतदान के दौरान जो दृश्य सामने आये हैं वे इस चुनावी लोकतंत्र के चुनावी उत्सव के लिए शर्मनाक हैं। समाजवादी पार्टी की शिकायत पर चुनाव आयोग को लोगों की आईडी की जांच करने और उन्हें वोट देने से रोकने के आरोप पर पांच पुलिस कर्मियों को निलम्बित करना पड़ा। समाजवादी पार्टी ने शिकायत की थी कि ये पुलिस कर्मी मतदाताओं की आईडी चेक करके लोगों को भयभीत कर रहे हैं और उन्हें बूथ पर नहीं जाने दे रहे हैं। इस मामले में मुरादाबाद में एक, कानपुर और मुजफ्फरनगर में दो-दो पुलिस कर्मी सस्पेंड किए गए वहीं मुरादाबाद में सात पुलिस कर्मियों को चुनाव ड्यूटी से हटाया गया। वहीं कुंदरकी के सपा प्रत्याशी का आरोप है कि डीएम और पुलिस अधिकारियों ने अपने सामने यूथ कैप्चरिंग कराई है। जिस प्रकार की वीडियो सामने आयी है उसमें पुलिस अधिकारी पिस्टल तानकर लोगों को दौड़ा रहा है, जब महिलाएं अपना मतदान पर्ची दिखाते हुए घर से बाहर निकल कर आ रही हैं। इससे यसै लगता है कि पुलिस किस अधिकारी के इशारे पर यह काम कर रही थी भले ही उसकी ड्यूटी निर्वाचन आयोग के हिस्से की रही हो। पहले जो काम दबंग करते थे। दलित बस्तियों के वोट नहीं डालने दिये जाते थे अब वह काम पुलिस कर रही है। वह मुस्लिम बस्तियों के वोट न पड़ सकें इसलिए उन्हें गलियों में घेर रही है। जितनी बड़ी संख्या में इन गलियों में पुलिस की तैनाती दिखी उससे इनका आशय स्पष्ट हो जाता है। भले ही पुलिस अधीक्षक इसकी काट तैयार किये हों कि पुलिस विवाद हो जाने पर गई थी। इस प्रकार की स्थितियां कई जगहों पर दिखीं। यानी जिस पुलिस और प्रशासन पर अधिक से अधिक वोट डलवाने और सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है वे खास समुदाय के वोट न पड़ सकें इसके लिए मुस्तैद दिखे। अब यह देखना तो चुनाव आयोग को है कि वह इसे किस रूप में लेता है। आखिरकार चुनाव आयोग ने पुलिस के खिलाफजो कार्रवाइयां की हैं उससे पुलिस को शर्म से गड़ जाना चाहिए कि वह कौन सा दायित्व निभा रही है।

प्रदेश में जिन नौ विधानसभा की सीटों पर चुनाव हुए उनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जीती थीं। भाजपा गठबंधन ने चार सीटें जीती थीं रालोद के लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ जाने से मीरापुर की सीट जिसे सपा और रालोद गठबंधन से रालोद ने जीती थी, वह रालोद के खेमे की यानी भाजपा की सीट मानी जा सकती है। इस प्रकार भाजपा गठबंधन के पास मझवां, गाजियाबाद, खेर और फूलपुर सीट थी। सपा के पास कुंदरकी, सीसामऊ, करहल और कटेहरी सीट थी। इसमें कुंदरकी और सीसामऊ सीट मुस्लिम प्रभावावाली सीट मानी जाती है। यही कारण है कि इन्हीं सीटों पर सबसे ज्यादा पुलिस बल की निगाह रही।

यह सीटें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नाक का सवाल बनी हुई हैं क्योंकि उपचुनाव को आगामी चुनाव का संकेतक माना जाता है और आमतौर पर यह माना जाता है कि उपचुनाव सत्तारूढ़ दल के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। यद्यपि इसके परिणामों से विधानसभा में सरकार के संख्याबल का कोई खास महत्व नहीं है लेकिन भाजपा सरकार लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला इन सीटों की जीत से लेने के लिए इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना चुकी है।

कातिल पत्नी: महिला ने युवक को उतारा मौत के घाट

रायगढ़। लैलूंगा थाना क्षेत्र के ग्राम पहाड़लुडेग निवासी निलांबर यादव (28) उनकी पत्नी तिलासो माझी टांगी से हमला कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि महिला ने चरित्र शंका और प्रताड़ना से तंग आकर यह कदम उठाया था। मृतक के चचेरे भाई सेतराम राउत ने पुलिस को बताया कि निलांबर आठ साल पहले तिलासो माझी को पत्नी बनाकर घर लाया था। दोनों का चार साल का बेटा भी है। घटना के दिन गांव में कार्तिकेश्वर मेला था, जहां परिवार के अन्य सदस्य गए थे। सुबह निलांबर की हत्या की सूचना मिलने पर घर पहुंचे तो शव खाट पर पड़ा मिला। अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। लैलूंगा थाना प्रभारी और उनकी टीम ने जांच तेज की। घटनास्थल की गहन पड़ताल और डॉग स्क्वाड की मदद से सबूत जुटाए गए। पूछताछ के दौरान पत्नी तिलासो माझी पर शक गहराया। कड़ी पूछताछ में तिलासो ने बताया कि उसने 16 नवंबर को भोर में अपने पति निलांबर यादव की हत्या की। आरोपी महिला ने बताया कि मेला देखने के बाद रात तीन बजे वह घर लौटी और पति के साथ सो गई। सुबह जब वह दोबारा मेला जाने की तैयारी कर रही थी तो दोनों में झगड़ा हुआ। चरित्र शंका और प्रताड़ना से परेशान होकर उसने घर में रखी टांगी से निलांबर के गले पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घूँघट की बगावत

24 नवम्बर 2024

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

मंच, महाराज और महाना से कैसी दिक्कत..!

स्वामी रामभद्राचार्य महाराज नें एक मंच से सतीश महाना से सिफारिस क्या कर दी कुछ होशियार चंदो को नानी याद आ गई, ओह ! माफ कीजियेगा उन होशियार चंदो को धरतीपुत्र याद आ गए जो डंके की चोट पर अपने दरबारियों में से अपने बिरादरी वालों को खोज - खोज कर सरकारी नौकरी देते थे ताकि चुनाव के समय जब ये मतदान अधिकारी, बीएलओ इत्यादि बने तो नेता जी की पार्टी को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचा सकें और होता भी वही था।इधर मोई जी के अब तक यह बात पल्ले ना पड़ी। महाराज जी यह बात जानते थे इसलिए सम दिन पूर्व आपने ब्राह्मण वर्गीकरण किया, उसके बाद अपने चेले के लिए मंत्री जी से मंच पर सरकारी नौकरी पक्की करवाई तब हंगामा करनें वाले आपके आलोचक थे जो निराबुद्धि जीव रहें होंगे और अब नयी घोषणा कि कुंभ के बाद पाकिस्तान खल्लास। ठीक है हो जावे तो, पन स्वामी जी कहीं न हुआ तो फिर ये दुमछल्ले भारत को सर पर उठा लेंगे। नेताओं का क्या कुछ भी बोल देते हैं.... चलता है लोग जानते हैं वादे नारे। गुब्बारों का सत्य, पर एक संत कहे और कर न पाए सवाल संत पर नहीं सनातन पर उठेगा। मंच पर मंत्री महाना से नौकरी मांग आपने ये ज्ञान सामान्य जन को दिया कि उसके बच्चे जो दिन रात किताबों में खोपड़ी दिये हैं वो सनातन के पुठ्ठे हैं। मंत्री जी के गुरु जी की सेवा में जुट नौकरी डायरेक्ट मिल जाती है। ऐसी ही गुरु चेला नौकरी प्राप्ति योजना के लिए सरकार हर वेकेंसी के बाद कोर्ट में बेईमान साबित हो जाती है पर यह पद्धति हजारों वर्षों पुरानी है वरना बीएचयू और अलाहाबाद यूनिवर्सिटी के गुरुओं के चेले मुफ्त में प्रोफेसर थोड़े बन पाते ! खैर जन कल्याण संत का कार्य है।आपने भी वही किया मंच से लोगों की आँखें खोल कर। पंडित जी लोगों में कौन निम्न उच्च के झगडे में अपन जाते नहीं क्यूंकि अपन खुद पंडित जी है। अपने मित्रों में दीक्षित, तिवारी, पाण्डेय ज्यादा हैं तो इनका भी सपोर्ट। अब पाकिस्तान का अंत, स्वामी जी थोड़ा साफ कर देते तो बेहतर, पाकिस्तान की जियोग्राफी खत्म होगी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, मतबल कैसे खत्म होगा ! फिर भी खत्म कर ही रहे हो तो कोंगियो की ताजा तरीन मोहब्बत का ख्याल रखना। उनके लोगो को बख्स देना फिर दो और घर में पहले से मौजूद तीन साथ में आपका आशीर्वाद लेने आएंगे अगर उनके चरण छूने से आप का धर्म भ्रष्ट और नष्ट न हो एक बात तो मानना पड़ेगा कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं,कल फलाने जी को बाहर देख यही बात साबित हुई,वरना महीनों से पुलिस के चक्कर में जेल में थे, पुलिस का तो जानते ही हैं, पर आखिरकार दूध का दूध पानी का पानी हो ही गया, हफ्तों अखबारों में उनके बारे में अनाप-शनाप खबरें छपती थी कि इनोवा पर नीली बत्ती लगाकर अलाल गमछा पगड़ी वाले वसूली करते थे,बैंकों को उल्लू बनाकर करोड़ों रुपए मार दिए,कई सौ करोड रुपए का चूना लगा दिया बैंकों को, इस चक्कर में काफी दिन सपरिवार फरार रहे मारे मारे फिरे पर पुलिस से कौन बच पाया है आजतक सो पकड़ ही गए,जेल भी जाना पड़ा,पर भला हो भारत की महान न्याय व्यवस्था का,कल पता लगा उन्हें जमानत मिल ही गई,आगे पीछे बाइज्जत बरी भी हो जाएंगे,काफी परेशान हुए पर अंत भला तो सब भला, होता है कभी-कभी समय खराब होता है तो यह सब दिक्कतें आती हैं,खैर पूछना ये था कि फिर तो वह सारी संपत्ति और पैसा उनका हो जाएगा ना जो उन्होंने बैंकों को चूना लगा कर कमाया था? अपना थोड़ा मन आशंकित हो गया है।हिन्दू और हिन्दुत्व के खिलाफ बोलने से क्या क्या मिलता है ? बौद्धिक होने का लाइसेंस मिलता है।जेएनयू , जामिया और एएमयू में प्रोफेसर की पोस्ट मिलती है।कनाडा और अमेरिका का वीजा मिलता है।प्रगतिशील होने का लाइसेंस मिलता है। विपक्ष से संसद या विधानसभा का टिकेट मिलता है। और मिलता है मैग्सेसे पुरस्कार ? नोबल भी संभव ? खैर जो भी हो प्रभु उड़ा डालो उस्तान को हमरा सपोर्ट रहेगा।

पंकज सीबी मिश्रा
जौनपुर, यूपी

जिंदगी का सफर

हर कदम पर नवीनतम व्यवहार मिलेगा
कभी गम तो कभी दर्द का बहाव मिलेगा
उम्र बढ़ती नहीं यह बस घटती ही जाती है
यूं जिंदगी का सफर तो कटती ही जाती है
जीवन के न जाने कितनी और पड़ाव है
कहीं दर्द तो कहीं मिलता हमें ठहराव है
दर्द हो या गम ये बस चलती ही जाती है
यूं जिंदगी का सफर तो कटती ही जाती है
संभावनाओं की तलाश में गुजर जाती है
कभी अपनो के अहसास में गुजर जाती है
दर्द का ताल हर हाल,ठहरती ही जाती है
यूं जिंदगी का सफर तो कटती ही जाती है
नए लोग जुड़ते जाते हैं जीवन संघर्ष मे
कुछ छूटते तो कुछ जुड़ते जाते है हर्ष में
स्थिति वक्त के साथ बदलती ही जाती है
यूं जिंदगी का सफर तो कटती ही जाती है
दुख हो चाहे सुख हो आगे बढ़ना पड़ता है
हालात जैसे हो जीवन से लड़ना पड़ता है
समय के साथ हालत बदलती ही जाती है
यूं जिंदगी का सफर तो कटती ही जाती है
हम सभी तो बंदर हैं जगत के मदारी के
कैसे नचायेगा यह निर्णय तो है मुरारी के
उसके इशारे पर खेल चलती ही जाती है
यूं जिंदगी का सफर तो कटती ही जाती है

प्रमेशदीप मानिकपुरी
आमाचानी
धमतरी छ ग

शरीफों से कौन मिलता है

इस जमाने में शरीफों से कौन है मिलता
टूटे दिल के टुकड़ों को कौन है सिलता
पड़ोसी को सुखी देख कर दुखी रहते हैं सारे
दूसरे को सुखी देख चैन कहाँ है मिलता
कैसे गिराएं लगे रहते हैं इसी उधेड़ बुन में
बिना किसी का अनिष्ट किये है चैन कहां मिलता
बरसात आने पर ही बरसती हैं बूंदें
बिना मौसम के है फूल है कहां खिलता
शहर में चर्चे होते है बदमाशों के
सत्ता के गलियारों में अपनी चमक है दिखाते
ठाठ से रहते हैं कोई उनका नहीं कुछ बिगाड़ पाता
शरीफ तो गुमनामी में ही मर हैं जाते
हद से ज्यादा शरीफ होना भी है एक गुनाह
शराफत का सब हैं फायदा उठा जाते
अपना उल्लू सीधा करके नजर नहीं हैं आते
शरीफ के कंधे पर रखकर बंदूक हैं चलाते

रवींद्र कुमार शर्मा
घुमारवीं जिला
बिलासपुर हि प्र

दिल्ली का लगातार वायु प्रदूषण संकट

भारत अपने विषैले धुएँ को साफ करने में क्यों विफल रहा है? राज्य के अधिकारी एक प्रायोगिक योजना का प्रचार करते हैं जिसमें बारिश के लिए बादलों को उत्तेजित करना शामिल है, लेकिन वैज्ञानिक संशय में हैं। तकनीकी प्रगति और नीतिगत हस्तक्षेपों के बावजूद दिल्ली को अक्सर दुनिया भर में सबसे प्रदूषित शहरों में से एक माना जाता है, जहाँ वायु गुणवत्ता में गंभीर गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। नवंबर 2024 में, वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर स्तर को पार कर गया, जो कुछ क्षेत्रों में 500 तक पहुँच गया, जो 400 की गंभीर सीमा से कहीं अधिक है। यह भयावह स्थिति शहर के बढ़ते प्रदूषण संकट से निपटने के लिए प्रभावी, दीर्घकालिक समाधानों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। सामान्य वायु प्रदूषण भारत में अपनी आधी से अधिक बिजली बनाने के लिए कोयले को जलाने से जुड़ा है। दिल्ली में, यह लाखों कारों से होने वाले उत्सर्जन और निर्माण उद्योग से निकलने वाले धुएँ के साथ मिलकर काम करता है, जहाँ कोई प्रदूषण नियंत्रण नहीं है। कुछ लोग अक्टूबर के अंत में हिंदू रोशनी के त्यौहार दिवाली के दौरान पटाखों के व्यापक उपयोग को भी इसके लिए दोषी ठहराते हैं। अधिकारियों ने 2017 में पारंपरिक पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था और लोगों को केवल पर्यावरण के अनुकूल रोशनी का उपयोग करने की अनुमति दी थी, लेकिन नियम को ठीक से लागू नहीं किया गया।पीएम2.5, प्रदूषित हवा में मौजूद सूक्ष्म कण पदार्थ, फेफड़ों में गहराई तक जाकर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन या हृदय की स्थिति वाले लोगों के लिए। हर साल, भारत में श्वसन सम्बंधी बीमारियों से सैकड़ों हजार लोग मरते हैं। 2021 में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में पाया गया कि भारत का कोई भी शहर प्रति घन मीटर हवा में 5 माइक्रोग्राम पीएम2.5 के अद्यतन विश्व स्वास्थ्य संगठन सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करता है। भारत के लगभग आधे राज्य इस सीमा को 10 गुना से भी ज्यादा पार कर गए हैं। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और निजी वाहनों की बढ़ती संख्या कण पदार्थ उत्सर्जन में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है। सफर इंडेक्स से पता चलता है कि वाहन प्राथमिक प्रदूषक हैं, जो पीएम2.5 उत्सर्जन में लगभग 40 प्रतिशत और नाइट्रोजन ऑक्साइड में 81 प्रतिशत का योगदान करते हैं। पुरानी तकनीक और उचित उत्सर्जन नियंत्रण की कमी के कारण दिल्ली और उसके आसपास के उद्योग जहरीली गैसें छोड़ते हैं। एनजीटी ने सीपीसीबी द्वारा प्रस्तुत क्षमता रिपोर्ट के आधार पर जिगजैग तकनीक वाले ईंट भट्टों सहित सभी ईंट भट्टों को बंद करने का निर्देश दिया है। पंजाब और हरियाणा में फसल अवशेषों को जलाने से दिल्ली की हवा में भारी मात्रा में धुआं और कण निकलते हैं। एनसीआर में चल रही निर्माण परियोजनाओं से अपर्याप्त नियंत्रण उपायों के कारण बड़ी मात्रा में धूल उत्पन्न होती है। राजमार्गों और मेट्रो लाइनों के निर्माण से परियोजना निष्पादन के दौरान पीएम10 के स्तर में वृद्धि हुई है। भारत-गंगा के मैदान में दिल्ली का स्थान और सर्दियों के दौरान कम हवा की गति प्रदूषकों को फंसाती है, जिससे घने धुएँ की परत बनती है।

दिल्ली के वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए निवारक उपाय स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है जैसे सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन और हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ ईंधन पर स्विच करना वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को काफी हद तक कम कर सकता है। दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत, सभी डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को 2023 तक अपने बेड़े का 50% और 2025 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना होगा। किसानों को बायो-डीकंपोजर और नो-बर्न तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने से पराली जलाने में कमी आ सकती है। महाराष्ट्र में सगुना चावल तकनीक पराली जलाने को कम करती है। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ाने से निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो सकती है, जिससे उत्सर्जन पर अंकुश लग सकता है। दिल्ली मेट्रो चरण चतुर्थ का विस्तार कनेक्टिविटी में सुधार और यातायात से सम्बंधित प्रदूषण को कम करने का लक्ष्य रखता है। पूसा द्वारा विकसित बायोडीकंपोजर का उपयोग पराली प्रबंधन के महत्त्वपूर्ण विकल्पों में से एक है।

निर्माण स्थलों पर पानी का छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन जैसे धूल दबाने वाले पदार्थों के इस्तेमाल को अनिवार्य करना। 2021 की सर्दियों के दौरान, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने आपातकालीन उपायों की एक शृंखला शुरू की, निर्माण पर प्रतिबंध लगाया, तीव्र धूल नियंत्रण उपायों को लागू किया। हरित स्थानों का विस्तार करना और सड़कों के किनारे पेड़ लगाना प्राकृतिक वायु शोधक के रूप में कार्य कर सकता है। नगर वन योजना एनसीआर उप-क्षेत्रों में हरियाली के लिए एक अवसर है। दिल्ली के वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय। महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में स्मॉग टावर लगाने से स्थानीय स्तर पर प्रदूषक स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। कॉनॉट प्लेस के स्मॉग टावर ने प्रदूषण के चरम समय के दौरान वायु गुणवत्ता में स्थानीय सुधार दिखाया है। वास्तविक समय प्रदूषण निगरानी सेंसर जैसे उन्नत निगरानी उपकरण लक्षित हस्तक्षेपों के लिए सटीक डेटा प्रदान कर सकते हैं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग दिल्ली की वायु गुणवत्ता संकट को दूर करने के लिए अंतर-राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देता है।

दिल्ली के वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए निवारक उपाय स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है जैसे सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन और हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ ईंधन पर स्विच करना वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को काफी हद तक कम कर सकता है। दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत, सभी डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को 2023 तक अपने बेड़े का 50% और 2025 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना होगा। किसानों को बायो-डीकंपोजर और नो-बर्न तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने से पराली जलाने में कमी आ सकती है। महाराष्ट्र में सगुना चावल तकनीक पराली जलाने को कम करती है। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ाने से निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो सकती है, जिससे उत्सर्जन पर अंकुश लग सकता है। दिल्ली मेट्रो चरण चतुर्थ का विस्तार कनेक्टिविटी में सुधार और यातायात से सम्बंधित प्रदूषण को कम करने का लक्ष्य रखता है। पूसा द्वारा विकसित बायोडीकंपोजर का उपयोग पराली प्रबंधन के महत्त्वपूर्ण विकल्पों में से एक है।

पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं पर जनता को शिक्षित करना, जैसे कि वाहनों को निष्क्रिय रखना, प्रदूषण के स्तर को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ जैसे अभियान उत्सर्जन को कम करने के लिए व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करते हैं। सामान्य वायु प्रदूषण भारत में कोयले को जलाने से जुड़ा है, जिससे इसकी आधी से ज्यादा बिजली पैदा होती है। दिल्ली में, यह लाखों कारों से निकलने वाले उत्सर्जन और निर्माण उद्योग से निकलने वाले धुएँ के साथ मिलकर होता है, जहाँ प्रदूषण नियंत्रण नहीं है। अक्टूबर से जनवरी तक यह संकट और गहरा जाता है, जब ठंड के मौसम के साथ-साथ बड़े पैमाने पर फसल के ठूंठ जलाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के पड़ोसी राज्यों से धुआँ आता है, क्योंकि हजारों किसान फसल के मौसम के बाद कृषि अपशिष्ट जलाते हैं। हालाँकि, सर्दियों की भारी हवा प्रदूषकों को जमीन के करीब फँसा देती है, जिससे धुआँ और भी खराब हो जाता है।

डॉ. सत्यवान सौरभ

वीरता की दास्तां कहता रेजागला का युद्ध

ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी...देशभक्ति की भावना से भरा यह गीत हमें विभिन्न राष्ट्रीय पर्वों तथा वीरता से संबंधित कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर पर बजता सुनाई देता है। इस गीत को सुनकर शरीर के रोम रोम में देशभक्ति की भावना हिलोरे मारने लगती है, आंखों डबडबा जाती है, दिल में एक एक सी उठती है। इस गीत को कवि प्रदीप ने लिखा था और भारत रव, सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने दिल्ली के रामलीला मैदान में पहली बार गाया गया था। इस गीत के लेखन की प्रेरणा रेजांगला के वे बीर थे जिन्होंने भारत चीन के मध्य हुए युद्ध में अतुलनीय पराक्रम दिखाया था। इस गीत में वर्णित दस-दस को एक ने मारा रेजांगला के मोर्चे पर भारत और चीन के सैनिकों के मध्य हुए युद्ध की सच्चाई है। इस गीत के हर शब्द उन रणबांकुरों की शीयं गाथा कहते है, जिन्होंने रेजागं ला के युद्ध में चीन के साथ मुकाबला करते हुए 18000 फीट की ऊंची बफीलीं चोटी पर वीरता और बलिदान की अमर गाथा लिखी थी। 18 नवंबर 1962 की रात में साढ़े तीन बजे बफीलें तूफान के बीच चीनी सैनिक हमारे सीमा क्षेत्र में घुस चुके थे। सुबह के 4.35 बजे जय मौसम थोड़ा ठीक हुआ तय अचानक चीनी सैनिकों ने 13 कुमाऊं रेजिमेंट को चार्ली कंपनी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। चीनी सेना के पास उस समय के अत्याधुनिक हथियार थे, और 13 कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों के पास 303 राइफल, 2 इंच मोटार और मशीन गन जैसे छोटो मारक क्षमता वाले हथियार और 1000 गोले थे। चीन की सेना को योजना लेह और चुकूल रोड लिंक जो कि दुंगती होकर जाता था, उसको अवरुद्ध करने की थी। मेजर शैतान सिंह और चाल कंपनी के जवानों ने इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया।

मेजर शैतान सिंह अपने संख्या बल और हथियारों की मारक क्षमता से परिचित थे। उन्होंने अपने सैनिकों को निर्देश दिया कि कारगर रेंज में आने पर ही फायर खोला जाए। रेंज में आते ही चालों कंपनी के योरों ने राइफल, मोटार और मशीन गन से हमला बोल दिया। एकाएक हुए इस हमले से चीनी सैनिक घबराकर इधर उधर भागने लगे। देखते हो देखने पहाड़ी की तलहटी चीनी सैनिकों की लाशों से पट गयी। चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना की एक कंपनी को दस गुना ज्यादा शक्ति से हमला किया था लेकिन भारतीय सेना के शौर्य के आगे उन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने कंपनी को धेरकर चौतरफ और ज्यादा तीव्र हमला किया मोटारों से हो रहे इस हमले में चाली कंपनी के संकर, हथियार बर्बाद होने लगे लेकिन भारतीय सैनिक

पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। गोला बारूद खत्म होने लगा था लेकिन भारतीय सैनिकों का जोश सातवें आसमान पर था। भारतीय सैनिक थंकरों से बाहर आ गये और संगीनों, राइफलों के वटों तथा हाथों से गुत्थमगुत्था का युद्ध आरम्भ हो गया। इसी बीच मेजर शैतान सिंह को गोली लग गयी और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हवलदार हरफूल सिंह उन्हें वहां से सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहते थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने अपनी बेल्ट को कमर से निकाल कर हवलदार हरफूल सिंह को पकड़ा दिया और कहा कि में अंतिम सांस तक लड़ूंगा। उन्होंने हवलदार हरफूल सिंह को कहा कि आप छावनी में जाकर बता दो कि चाली कंपनी का हर जवान लहू की आखिरी बूंद और आखिरी गोली तक लड़ा। इसी बीच मशीनगन का एक बस्ट मेजर शैतान सिंह की जांघ, पेट और सीने को पार कर गया। इस हमले में मेजर शैतान सिंह और उनके 114 जवान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गये। लद्दाख के रेजांगला में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चाल कंपनी के कुल 124 जवान थे। उन्होंने अपने अदम्य शीर्ष और पराक्रम के बल पर 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया और लगभग तीन हजार सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इस युद्ध में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चालों कंपनी के 114 जवान लड़ते लड़ते योगति को प्राप्त हो गये थे। इस टुकड़ी का नेतृत्व मेजर शैतान सिंह कर रहे थे। मेजर शैतान सिंह के साहस और वीरता के सम्मान के लिए उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता सम्मान 'परमवीर चक्र' से सम्मानित किया गया और उनकी रेजिमेंट के आठ जवानों को और चक्र, चार को सेना मेडल तथा एक को मैशन इन डिस्पैच प्रदान किया गया। यह लड़ाई भारतीय सैन्य इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि चीन ने इस लड़ाई में भारतीय सैनिकों के पराक्रम को देखकर युद्धविराम की घोषणा की थी। रेजांगला के उन वीरों के शौर्य पराक्रम, साहस और वीरता को देखकर चीनी सैनिक भी नतमस्तक हो गए थे। उन्होंने रेजांगला के उस बुद्ध स्थल पर एक पट्टी पर 'ब्रेव' लिखकर वीर सैनिकों के शवों के पास सम्मानपूर्वक रख दिया था और उन वीरों के सम्मान में जमीन पर संगीन को गाड़कर उस पर कैप लटकाकर चले गए थे। रेजांगला के युद्ध में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चालों कंपनी के वीरगति प्राप्त करने वाले सैनिकों में हरियाणा के 64, राजस्थान के 25, उत्तर प्रदेश के 23, बिहार के 01 और पंजाब राज्य के 01 सैनिक थे रेजांगला की लड़ाई में वीरगति को प्राप्त करने वाले सैनिकों की याद में भारतीय सेना द्वारा लख के चुशूल में युद्ध स्मारक बनाया गया है। उस स्मारक पर अंग्रेजी में उन वीर सैनिकों के नाम लिखे गये हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी सांसें कुर्बान कर दी थीं। इस स्मारक में एक शिलालेख लगाया गया है जिसमें पहली चार पंतिया कविता 'रेशियस' से उद्धृत की गई हैं। इस स्मारक के ठीक सामने समाधि के रूप में अराम' स्मारक का निर्माण किया गया है। उल्लेखनीय है कि 13 कुमाऊं रेजिमेंट को चालों कंपनी के बीरगति प्राप्त करने वाले सभी जवान अशेर (यादव) थे। इस युद्ध में चालों कंपनी की अभूतपूर्व बीरता को देखते हुए, वीरों के सम्मान में चार्ली कंपनी का नाम बदलकर रेजांगला कंपनी कर दिया गया है।

हरियाणा में रेज्यंग ला शीयं समिति द्वारा अहिरवाल क्षेत्र के रेवाड़ी शहर में धारूहेड़ा चौक के पास रेजांगला पार्क के अंदर रेजांग ला युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया है। इस स्मारक में अपने फर्ज पर जीवन को होम कर देने वाले वीर जवानों के नाम अंकित हैं। समिति द्वारा जिला प्रशासन के और कुमाऊं रेजिमेंट के सहयोग से प्रतिवर्ष रेजांगला दिवस के अवसर पर स्मारक समारोह आयोजित किया जाता है, इसमें कुमाऊ रेजिमेंट और रेजांगला में वीरगति पाने वाले योर ओरों के परिवारों के सदस्य भाग लेते है। रेजांगला के बोरों के सम्मान में पिछले कुछ वर्षों से देश के कई राज्यों में सैनिक और सामाजिक संगठनों द्वारा रेजांगला दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। रायबरेली के सैनिक समाज सेवा संगठन द्वारा इस अवसर पर वीरगति प्राप्त सैनिकों और और नारियों और वोरता पदक विजेताओं के लिए एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

घूँघट की बगावत

24 नवम्बर 2024

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

क्या इंसानी मस्तिष्क की बराबरी करेगा नाबाओनिंस हेस्टिया

एक अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों को दावा है कि 80 लाख साल पहले के पक्षी के दिमाग की जांच से यह जानकारी मिली है कि आज के पक्षियों का दिमाग इतना विकसित हो गया है कि उसकी बराबरी सिर्फइन्सान का दिमाग ही कर सकता है। शोधकताओं के लिए यह एक पहेली है फिर भी उनके अध्ययन के नतीजे यह कहते हैं। शोधकर्ताओं का ऐसा दावा है कि आज के पक्षियों का दिमाग इतना विकसित है जिसकी बराबरी केवल इंसान ही कर सकते हैं. वैज्ञानिकों के लिए ये किसी पहेली से कम नहीं है।

वर्ष 2016 में जीवाश्म विज्ञानी विलियम नावा ने एक ऐसे छोटे जीवाश्म की खोज की थी, जिससे आधुनिक पक्षियों के दिमाग और बुद्धि से जुड़े कई रहस्यों का पता लगाया जा सका है। शोधकताओं ने हाल ही में माइक्रो सीटी स्कैन का इस्तेमाल करके इस पक्षी की खोपड़ी और मस्तिष्क की थ्रीडी इमेज बनाई है जिससे कई नई जानकारियां सामने आई हैं।

नाबाओनिंस हेस्टिया नाम के इस पक्षी के जीवाश्म की मदद से वैज्ञानिकों ने इसके दिमाग और कान की संरचना का सटीक पुनर्निमाण करने में कामयाबी हासिल की है. ये पक्षी लगभग 80 लाख साल पहले डायनासोर के साथ सूखे इलाकों में रहता था। यह डायनासोर के युग में मौजूद था। प्रतिष्ठित 'नेचर' पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन की केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जीवाश्म विज्ञानी गुईलेम नेवलॉन ने 'नायाब' खोज बताया है। अध्ययन से पता चला है कि जुरासिक काल के दौरान पक्षियों का विकास छोटे पंख वाले डायनासोर से हुआ था नावा ओनिस हेस्टिया नामक पक्षी के दिमाग के विकास का तुलनात्मक अध्ययन यही बताता है। ऐसा दावा है कि ये पक्षी लगभग 80 लाख साल पहले डायनासोर के साथ सूखे इलाकों में रहता था। इस खोज ने सबसे पहले ज्ञात पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स से जुड़े कई सवालों का जवाब दिया है जो लगभग डेढ़ करोड़ साल पहले यूरोप में रहते थे. नायाओर्निस के जीवाश्म की नई तस्वीरें इसे आधुनिक छोटे आकार के कबूतर जैसा प्रदर्शित करती हैं। लॉस एंजेलिस काउंटी के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के जीवाश्म विज्ञानी और अध्ययन के सह-प्रमुख लेखक लुइस चियाप्पे ने कहा, 'यह लंबे समय से खोजा जा रहा सबूत है क्योंकि प्रारंभिक पक्षियों की अच्छी तरह से संरक्षित थोडी खोपड़ी मिलना बेहद दुर्लभ है, और यह अब तक की सबसे अच्छी तरह से संरक्षित खोपड़ी है'।

अध्ययन के वरिष्ठ लेखक डेनियल फेल्ड ने कहा, 'वैज्ञानिकों को यह समझने में मुश्किल आयी कि पक्षियों का अनोखा मस्तिष्क और असाधारण बुद्धि कैसे और कब विकसित हुई. यह नई खोज काफी कुछ जानने में मदद करेगी।' नावाओनिंस की खोपड़ी का आकार आज के पक्षियों की तुलना में छोटा था, लेकिन आर्किगोप्टेरिक्स की तुलना में बड़ा था. इसका दिमाग आधुनिक पक्षियों और इंसानों की तरह रीढ़ की हड्डी से जुड़ा था जो आर्कियोप्टेरिक्स और डायनासोर से बिल्कुल अलग था। नवनिंस में कुछ अनूठी विशेषताएं पायी गई हैं जैसे कान के अंदर का एक हिस्सा दूसरे पक्षियों की तुलना में बड़ा था। नावाओनिंस एक ऐसे पक्षी समूह से संबंधित था जो गंभीर आपदाओं में भी जीवित रहा। इसकी पतली और नाजुक चोंच से पता चलता है कि ये कीड़े और बीज खाने के लिए बनी थी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखी 'द साबरमती रिपोर्ट'

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बहुचर्चित फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' देखी। फिल्म देखने के बाद सीएम योगी ने कहा कि मैं 'द साबरमती रिपोर्ट' की पूरी टीम को बधाई देता हूं जिन्होंने इस वास्तविक सच को देश की जनता के सामने फिल्म के माध्यम से बाहर लाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि हर भारतवासी को ह्रदय साबरमती रिपोर्टह्व फिल्म को देखनी चाहिए और गोधरा का सच के नजदीक जाने का प्रयास करना चाहिए। सीएम योगी ने फिल्म को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री करने की घोषणा की। सीएम योगी ने कहा देश के खिलाफ और सरकारों के खिलाफ राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए समाज में वैमनस्यता पैदा करने के लिए देश में जो कृत्य हुए हैं उसे देश की जनता को जानने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं उन चेहरों को पहचानने के साथ-साथ उनका पदार्फाश करने की भी आवश्यकता है। सीएम योगी ने कहा कि फिल्म की टीम ने सत्य उजाकर करने के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। फिल्म के माध्यम से वास्तविक सच को एक बड़े रूप में देश के सामने लाने का प्रयास

किया गया है। सीएम योगी ने कहा कि मामला अयोध्या से जुड़ा है, मैं घटना में मारे गए सभी राम भक्तों को श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के साहसिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए लोग इस सत्य को अधिक से अधिक देखें। सीएम योगी राज्य सरकार की ओर से ह्रद साबरमती रिपोर्टह्व फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की। इसके पहले सीएम योगी ने लखनऊ के प्लासियो मॉल के सिनेमाहॉल के ऑडी-07 में पूर्वाह्न 11:30 बजे के शो में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, महापौर सुषमा खर्कवाल, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सहित अनेक अनेक जनप्रतिनिधियों और शासन-प्रशासन के अधिकारियों के साथ फिल्म देखी। खास मौके पर फिल्म के मुख्य अभिनेता विक्रांत मैसी और फिल्म यूनिट से जुड़े लोगों की मौजूदगी रही। इससे पहले, बीते मंगलवार को विक्रांत मैसी ने सीएम योगी से भेंट की थी। बता दें कि 'द साबरमती रिपोर्ट' एक सत्य घटना पर आधारित एक बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन रंजन चांडेल द्वारा किया गया है। फिल्म में विक्रांत मैसी, राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा लीड रोल में हैं। यह फिल्म साल 2002 में हुई साबरमती एक्सप्रेस की दिल दहला देने वाली घटना से प्रेरित है। एकता कपूर इस फिल्म की निमार्ता है। 15 नवंबर को रिलीज हुई इस फिल्म की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भी तारीफ की है।

लगता है कि सोया हुआ संविधान जाग रहा

संविधान को कमजोर करने या संविधान की वैधानिकता को कमजोर करने का काम राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी कर रहे थे वे बार बार केशवानंद भारती मामले में प्रतिपादित खुनियादी तत्वों के सिद्धांत को चुनौती दे रहे थे और कह रहे थे कि इस फैसले को पलट दिया जाना चाहिए। संविधान रक्षा की सर्वाधिक कमजोर भूमिका हाल में स-ेवानिवृत्त हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने निभाई। एक तो उन्होंने अपने ढाई साल के कार्यकाल में लोगों के मौलिक अधिकारों की हिफाजत नहीं की और जाते जाते निजी संपत्ति के एक मामले में न्यायमूर्ति कृष्णा अमर के बहाने डॉ आंबेडकर के इरादों की गलत व्याख्या करते हुए समाजवादी सिद्धांत को स्वतंत्रता के मूल्यों के विरुद्ध बताया। जिसकी न्यायमूर्ति नागरता ने आलोचना भी की। संविधान के भाग तीन और चार को भुलाकर उसके बाकी हिस्सों को प्रासंगिक बनाने का अभियान व्यापक रूप से चलाया गया है। यह देश और संविधान का दुर्भाग्य है कि जिस संविधान को देश के नागरिकों को अभय बनाने के लिए सृजित किया गया था वह इनकाउंटर का शिकार होते, बुलडोजर का शिकार होते, भीड़ की हिंसा का शिकार होते या न के मानस में उलझते जाते नागरिकों की दैहिक और मानसिक रक्षा नहीं कर सका। संविधान में नागरिकों की बात की गई है और दलों यानी राजनीतिक दलों की बात नहीं की गई है। लेकिन राजनीतिक दल राज्य और संविधान सभी पर हावी है। राजनीतिक दलों की इसी बढ़ती शक्ति के बारे में विनोबा भावे ने कहा था कि ये तो संगठित गिरोह बन गए हैं। उनकी तुलना में संविधान में नागरिकों को अधिक महत्त्व दिया गया है और स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के मूल्य उसी के लिए सृजित किए गए हैं। ये सारे मूल्य और उनके हकदार नागरिक आज भी डरे और दुबके हुए हैं। संविधान का एक काम नागरिकों को अभय प्रदान करना भी है पर पिछले दस सालों में उसने सत्तारूढ़ दल को अभय बनाया है और विपक्ष से लेकर नागरिकों तक को भयभीत किया है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से संविधान जागा है उससे एक उम्मीद बनी है। संविधान इस लोकतंत्र का कालभैरव है। जिस तरह कालभैरव के किसी शहर की रक्षा करने की मान्यता है वैसे ही हम मान सकते हैं कि संविधान लोकतंत्र की रक्षा करता है। देवता की तरह संविधान भी दिखाई नहीं पड़ता भी उसकी परोक्ष उपस्थित लोकतंत्र को संरक्षित करती है। लेकिन यह संरक्षण तभी हो सकता है जब संविधान पर बहस और चर्चा प्राथमिक स्तर ऊपर उठे लोग धर्मग्रंथों से अधिक संविधान को मान्यता दें। यह राजनीतिक दलों और कार्यकताओं का कर्तव्य है कि संविधान के दर्शन, उसके बुनियादी मूल्यों की बहस को जनता के बीच में ले जाएं। यह कर्तव्य विश्वविद्यालयों का भी है कि वे अपने विद्यार्थियों की संविधान में प्रतिवद्धता पैदा करें। डॉ आंबेडकर ने लोकतंत्र को महज संस्थाओं में स्थित नहीं माना था। उनका कहना था कि संस्थाओं में तो गणतंत्र रहता है।

लोकतंत्र तो जनता के भीतर रहता है। लोकतंत्र एक संस्कृति है जिसके लिए सहभाव व साझापन होना चाहिए और सहमनापन होना चाहिए। फिर भी एक अच्छी स्थिति यह बनी है कि मनुस्मृति और कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो के आधार पर देश का निर्माण करने का प्रयास करने वाले अपनी जिद छोड़कर संविधान की सही और गलत व्याख्या के आधार पर बहस कर रहे हैं। वामपंथ से दक्षिणपंथ तक कोई भी संविधान को खुलेआम चुनौती नहीं दे रहा है। गोपनीय एजेंद्र किसी का कुछ भी हो सकता है लेकिन संविधान के आगे शाम होने या उसे सलाम करने का दौर चल रहा है। संविधान के प्रति यही अदब एक उम्मीद जगाता है और लगता है कि सोया हुआ संविधान जाग रहा है।

▸ फिर विवादों में घिरी ऐंजेलिना जोली

लॉस एंजिल्स की एक महिला ने लगाए जादू-टोना करने जैसे गंभीर आरोप

जोली के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे में महिला ने आरोप लगाया है कि अभिनेत्री कई लोगों के माध्यम से उन्हें परेशान कर रही हैं। इतना ही नहीं महिला ने यह भी कहा है कि अभिनेत्री ने उसकी हत्या करने की कल्पना भी की है।

अभिनेत्री एंजेलिना जोली के निजी जीवन के कलेश कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तरफ जहां अभिनेत्री पूर्व पति ब्रैड पिट के साथ एक वाइनरी एस्टेट को लेकर कानूनी लड़ाई में उलझी हुई थी। वहीं, अब एक नया कलेश उनके सामने खड़ा है। दरअसल, एक महिला ने एंजेलिना पर जादू-टोना करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं लॉस एंजिल्स की इस महिला ने अभिनेत्री पर सम्मोहन संबंधी धमकियां देने का आरोप भी लगाया है।

जोली के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे में महिला ने आरोप लगाया है कि अभिनेत्री कई लोगों के माध्यम से उन्हें परेशान कर रही हैं। इतना ही नहीं महिला ने यह भी कहा है कि अभिनेत्री ने उसकी हत्या करने की कल्पना भी की है। महिला ने कहा है कि जोली 2010 से उसके घरों का पीछा कर रही है। ज्ञानवर्धक सूत्र बताते हैं कि द मिरर द्वारा प्राप्त अदालती दस्तावेजों में, अज्ञात महिला का दावा है कि जोली 'मानसिक रूप से पागल है और मेरे साथ संबंध होने का विरोध करती है। जब वह स्पष्ट रूप से विक्षिप्त नहीं है, तो उसे मानसिक-दोषपूर्ण विकार हैं। महिला का आरोप है कि अभिनेत्री ने नो-कॉन्टैक्ट ऑर्डर का उल्लंघन करते हुए तस्करी के लिए जादू टोना किया। इन सब के अतिरिक्त, महिला ने दावा किया कि हॉलीवुड की स्टार अभिनेत्री कथित तौर पर अन्य उत्पीड़न-संबंधी अपराधों से जुड़े एक बाल तस्कर की भी सहायता कर रही थी। इस महिला ने अपने पिता को अपना गवाह बनाया है। महिला ने दावा किया है कि उसके पिता ने इन व्यवहारों को देखा है। उन्होंने अभिनेत्री पर दूसरे लोगों के बच्चों की हत्या करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'तस्करी के लिए गैरकानूनी काम करना बंद करें। इस तथ्य को स्वीकार करें कि लोग आपके व्यवहार से पीड़ित होने को बर्दाश्त नहीं करेंगे।'

समय की धारा में.....

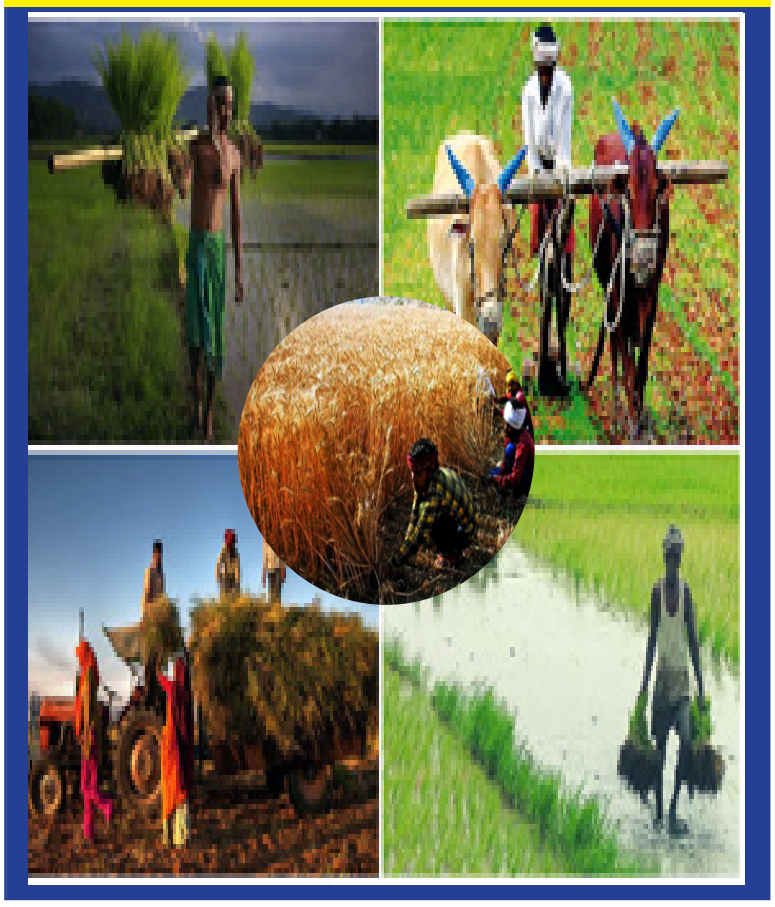

गोधरा ट्रेन की कहानी को संवेदनशीलता और तथ्यों प्रस्तुत करती 'द साबरमती रिपोर्ट'

' 12वीं फेल' के बाद, फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर क्रिटिक 2023 विजेता विक्रांत मैसी अपनी फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' के साथ बड़े पर्दे पर वापस आ गए हैं।

यह फिल्म कई कारणों से लंबे समय से चर्चा में है, जैसे निर्देशक में बदलाव, रिलीज की तारीख में देरी और ट्रेलर की प्रतिक्रियाएं। लेकिन अब यह फिल्म सिनेमाघरों में आ गई है, जिसमें विक्रांत मैसी के साथ रिद्धि डोगरा और राशि खन्ना भी हैं। हाल ही में 'सिंघम अगेन' और 'भूल भुलैया 3' जैसी घटिया दिवाली रिलीज के साथ, 'द साबरमती रिपोर्ट' अलग है, कहानी के मामले में बेहतर है, और दर्शकों को सबसे घातक भारतीय दंगों में से एक के दौरान खोई गई निर्दोष जिंदगियों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। निमार्ता एकता कपूर और निर्देशक धीरज सरना की 'द साबरमती रिपोर्ट' का दावा है कि इसने भारत की एक ऐसी ऐतिहासिक घटना की कहानी को पर्दे पर उतारा है, जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा, पढ़ा और सुना जा चुका है, लेकिन क्या यह सब सच है? निमार्ताओं ने इस घटना में एक नया पहलू जोड़ने की कोशिश की है।

फिल्म भारतीय मीडिया घरानों की भागीदारी और उसके पत्रकारों की दुविधा को उजागर करती है।

कथावस्तु

'द साबरमती रिपोर्ट' 2002 में गुजरात में हुए गोधरा कांड के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने से 59 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। फिल्म एक रिपोर्टर के जरिए इस बात पर प्रकाश डालती है कि यह एक दुखद दुर्घटना थी या कोई भयावह साजिश। हालांकि, जो लोग यह सोच रहे हैं कि इस फिल्म में गुजरात की घटना पर पहले बनी फिल्मों की तरह कोई पुराना कथानक होगा, तो शायद आप गलत हैं। निमार्ताओं ने साबरमती एक्सप्रेस की घटना को लेकर एक साहसिक दृष्टिकोण अपनाया है। फिल्म में हिंदी भाषी पत्रकारों और पश्चिमी मीडिया के बीच वैचारिक टकराव को भी दिखाया गया है, जो 'द साबरमती रिपोर्ट' को और भी दिलचस्प और वास्तविक बनाता है।

भारतीय इतिहास में रुचि रखने वालों को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए।

कहानी की शुरूआत इस रेल दुर्घटना की सच्चाई जानने की जद्दोजहद से होती है, जिसमें हिंदी भाषी पत्रकार समर कुमार (विक्रांत मैसी) और अंग्रेजी पत्र-ाकार मनिका राजपुरोहित के बीच सच और झूठ के बीच संघर्ष दिखाया गया है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब महिला पत्रकार अमृता गिल (राशि खन्ना) की एंट्री होती है और वह समर के अधूरे प्रयास को नए पंख देने के लिए इस पूरी घटना की जांच करती है।

क्या समर और अमृता इसमें सफल होते हैं? इसके लिए आपको यह फिल्म देखनी होगी।

▸ विक्रांत मैसी का कमाल

'द साबरमती रिपोर्ट' एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, इसलिए इस पर बहस हो सकती है कि यह फिल्म प्रामाणिक है या नहीं। लेकिन जैसा कि विक्रांत ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, इस फिल्म को हिंदू-मुस्लिम या लेफ्ट-राइट विंग के चश्मे से देखना मानवता के लिए शर्म की बात है।

अभिनय

'द साबरमती रिपोर्ट' में कलाकारों का अभिनय सराहनीय है। पत्रकारों की भूमिका निभाने वाले विक्रांत मैसी, राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा ने अपने अभिनय से कहानी को और भी गहरा बना दिया है। विक्रांत जैसे अभिनेता के लिए, जिन्होंने '12वीं फेल', ' सेक्टर 36' और 'डेथ इन द गंज' जैसी कई समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भूमिकाएँ निभाई हैं, 'द साबरमती रिपोर्ट' के साथ यह और भी बेहतर हो जाता है। इस फिल्म में उनका अभिनय पानी की तरह है; यह बहता है और शांत प्रभाव डालता है। राशि ने अपने किरदार में एक खास आकर्षण जोड़ा है, वहीं रिद्धि ने अपने प्रभावशाली अभिनय से सबका मन मोह लिया है। वह एक बॉस लेडी के किरदार में पूरी तरह से रम गई हैं और उसके साथ न्याय करती हैं।

एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स के मशहूर टीवी शो 'कुटुंब' में यश की भूमिका में नजर आने वाले अभिनेता धीरज सरना ने ' द साबरमती रिपोर्ट' का निर्देशन किया है।

जहां निमार्ताओं ने नानावटी-मेहता आयोग के निष्कर्षों पर कायम रहते हुए भी सरन के प्रयासों में अनुभव की कमी है; इसका सबूत आप फिल्म के कुछ दृश्यों को देखकर आसानी से देख सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर, इस गंभीर मुद्दे को पर्दे पर उतारने का उनका प्रयास अच्छा रहा है। इसके अलावा, लेखन में खामियों को अच्छे अभिनय और बैकग्राउंड स्कोर द्वारा उचित रूप से कवर किया गया है।

ट्रेन के जलने जैसे दृश्यों में वीएफएक्स तकनीक का अच्छा इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सिनेमैटोग्र-ाफी थोड़ी ठंडी लगती है। बतौर निमार्ता एकता कपूर ने दर्शकों को सिनेमाघरों में पैसे वसूल मनोरंजन देने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिल्म का खामोश हिस्सा इसकी लेखनी है। इसके अलावा, बीच-बीच में फिल्म थोड़ी सी पटरी से उतरती हुई नजर आती है, क्योंकि गुजरात दंगों से ज्यादा 'द साबरमती रिपोर्ट' दो लीग के पत्रकारों के बीच वर्चस्व की लड़ाई बन जाती है, लेकिन यह आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। इन पत्रकारों की भूमिका को फिल्म का केंद्र बिंदु कहा जा सकता है।

निष्कर्ष

'द साबरमती रिपोर्ट' एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, इसलिए इस पर बहस हो सकती है कि यह फिल्म प्रामाणिक है या नहीं। लेकिन जैसा कि विक्रांत ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, इस फिल्म को हिंदू-मुस्लिम या लेफ्ट-राइट विंग के चश्मे से देखना मानवता के लिए शर्म की बात है।

'द साबरमती रिपोर्ट' न केवल दंगों के दौरान मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि देती है, बल्कि एक मनोरंजन के माध्यम के रूप में अंत तक दिलचस्प भी बनी रहती है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।

संपादक: पंकज धर द्विवेदी

संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com